EDU TERIA
E - D.N.A
Daily Newspaper Analysis
Prelims Mains Essay
By- Nikhil Ranjan

Useful For Prelims

Date: 14 January 2026

गोवा मुक्ति आंदोलन में सुधाताई जोशी ने दिया था अहम योगदान

स्वतंत्रता सेनानी सुधाताई जोशी का जन्म 1918 में आज ही गोवा में हुआ था। गोवा मुक्ति संग्राम में शामिल महादेव शास्त्री जोशी से विवाह के बाद से वह भी इस आंदोलन से जुड़ गई। सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए गुप्त रूप से गोवा में प्रवेश किया। 1955 में मापुसा में गोवा कांग्रेस का पहला बड़ा सम्मेलन आयोजित किया। जब वह स्वयंसेवकों को संबोधित कर रही थीं, तभी एक पुर्तगाली अधिकारी ने बंदूक दिखाकर उन्हें रोका लेकिन वह निडर होकर बोलती रहीं। इसके बाद उन्हें 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जेल में स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण 1959 में उन्हें रिहा करना पड़ा।

Sci & Tech

बिगड़ते पर्यावरण के बीच प्रवासी पक्षियों ने राह बदली, देरी से पहुंच रहे

सुनील दत्त पांडेय

जलवायु

बिगड़ते पर्यावरण के चलते प्रवासी पक्षियों ने अपनी राह बदल दी है। उन्होंने केवल राह ही नहीं बदली बल्कि अपने आगमन के समय और तिथि में भी परिवर्तन किया है। इस बार विदेश से प्रवासी पक्षी जलवायु परिवर्तन के कारण एक पखवाड़े की देरी से उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में पहुंचे। पक्षी विज्ञानी और पर्यावरणविद् प्रोफेसर दिनेश भट्ट इसकी वजह जलवायु परिवर्तन मान रहे हैं। प्रोफेसर भट्ट का कहना है कि रूस, मध्य एशिया, स्कैंडिनेवियाई और यूरेशियाई देशों से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके प्रवासी पक्षी हर साल नवंबर-दिसंबर के महीने में हरिद्वार में नीलधारा, मिस्सरपुर आदि स्थानों पर गंगा के तट पर आते हैं।

प्रवासी पक्षियों में प्रवास एक प्राकृतिक पड़ाव है। बहुत ज्यादा ठंड के महीनों में प्रवासी पक्षी अपने देश में ठंड बढ़ने के कारण भारत आते हैं, परंतु इस बार लंबे मानसून के मौसम और जलवायु परिवर्तन के चलते एवं पिछले साल नवंबर-दिसंबर में बारिश-बर्फबारी न होने के कारण प्रवासी पक्षी रूस, मंगोलिया, साइबेरिया की तरफ से उत्तराखंड में 15 से 20 दिन की देरी के बाद पहुंचे। जाड़ों के समय में स्कैंडिनेवियाई और यूरोपीय देशों के ज्यादा हिस्सों में कई दिनों तक भारी बर्फबारी होती है। इसलिए ये पक्षी कई देशों और हिमालय को पार करके उत्तरी भारत के निचले इलाकों, खासकर उत्तराखंड में नवंबर के आखिरी और दिसंबर-जनवरी की शुरुआत में पहुंचते हैं।

युद्ध ने भी डाला असर

पक्षी विशेषज्ञ प्रोफेसर बी जोशी का कहना है कि रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध ने भी साइबेरियाई क्षेत्र से प्रवासी पक्षियों की आवाजाही पर गहरा असर डाला है। चार वर्षों से लगातार बमबारी के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, जिससे जलवायु प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत खतरनाक हो गई है। रूस-यूक्रेन की तरफ से अपने मूल निवास स्थान से हरिद्वार तक लंबी उड़ान भरने वाले पक्षियों की तादाद पिछले कई सालों के मुकाबले अत्यधिक कम रही है।

अंतरराष्ट्रीय पक्षी वैज्ञानिक और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के जंतु एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग के पूर्व प्रोफेसर डा. दिनेश भट्ट बताते हैं कि रूस, मध्य एशिया स्कैंडिनेवियाई यूरोपीय देशों में पक्षियों को बर्फबारी के कारण खाना मिलने में दिक्कत होती है और इसलिए वे हजारों किलोमीटर की यात्रा करके कम ठंडे इलाकों में पहुंचते हैं। वसंत ऋतु की शुरुआत में तापमान बढ़ने पर प्रवासी पक्षी फरवरी के आखिर और मार्च की शुरुआत में अपने मूल स्थान पर लौट जाते हैं। भारत में आने वाले ज्यादातर प्रवासी पक्षी यूरोप और मध्य एशिया से आसमान में केंद्रीय हवाई मार्ग से आते हैं और उसी रास्ते से वापस जाते हैं। वह कभी अपना रास्ता नहीं भटकते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में देखने में आया है कि साइबेरिया से क्रेन पक्षी उतराखंड में नहीं आ रहे हैं, जो चिंता का विषय है, क्योंकि पहले साइबेरियाई क्रेन पक्षियों के झुंड उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे काफी तादाद में आते थे। प्रोफेसर भट्ट इसका कारण जलवायु परिवर्तन मानते हैं। प्रोफेसर भट्ट का कहना है कि उन्होंने हरिद्वार की झिलमिल झील, देहरादून विकास नगर क्षेत्र में स्थित आसन बैराज और डाक पत्थर तथा ऋषिकेश में पशु लोक बैराज, पौड़ी गढ़वाल जिले में लैंसडाउन, कोटद्वार-कोलहू नदी का किनारा-राजाजी टाइगर रिजर्व, कार्बेट टाइगर रिजर्व, बद्रीनाथ मंदिर-शेष नेत्र झील-माणा पास और अन्य ऊंचे इलाकों में प्रवासी पक्षियों को लेकर विशेष अध्ययन किया है, यहां पर कई सालों से प्रवासी पक्षी लगातार आते हैं। पक्षी प्रेमी संदीप रावत ने बताया कि प्रवासी पक्षियों को इस महीने के आखिर में पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार एवं लैंसडाउन में दो दिवसीय स्नेह पक्षी महोत्सव में भी देख सकते हैं यह पक्षी महोत्सव इस साल 31 जनवरी एवं 1 फरवरी तक आयोजित होगा।

Hindustan Page

बड़ा फैसला

एनआइटी और आइआइएसईआर काउंसिल की बैठक में लिया गया निर्णय, 10 एनआइटी में तुरंत रिसर्च पार्क व 13 एनआइटी में बनाएंगे इनक्यूबेशन सेंटर, एमटेक के विशेष कोर्स शुरू होंगे, पीएचडी प्रोग्राम में 360 डिग्री का होगा बदलाव

सभी एनआइटी-आइआइएसईआर रिसर्च पार्क व इनक्यूबेशन सेंटर से होंगे लैस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देश को आत्मनिर्भर और 2047 तक विकसित बनाने के लिए लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआइटी) और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आइआइएसईआर) को लेकर मंगलवार को कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें ऐसे सभी एनआइआटी और आइआइएसईआर जल्द ही रिसर्च पार्क और इनक्यूबेशन सेंटर से लैस करने का फैसला लिया है, जिनमें अब तक ये नहीं हैं। इस दौरान 13 एनआइटी में इनक्यूबेशन सेंटर और 10 एनआइटी में तुरंत रिसर्च पार्क बनाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही दोनों शीर्ष संस्थानों ने अपने पीएचडी कार्यक्रमों में 360 डिग्री का बदलाव करते हुए उन्हें उद्योगों की मांग और समस्या आधारित रखने का फैसला लिया है।

एनआइटी और आइआइएसईआर की 13वीं काउंसिल की बैठक में दोनों ही शीर्ष तकनीकी व शोध संस्थानों में सुधार को लेकर ये निर्णय लिए गए हैं।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अगुआई में बुलाई गई शीर्ष बैठक में इन सभी संस्थानों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। बैठक में इनके पाठ्यक्रमों को एआइ, सेमीकंडक्टर जैसी उभरती हुई तकनीकों के साथ जोड़ने का भी फैसला लिया है ताकि 21वीं सदी में आत्मनिर्भर भारत और 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। काउंसिल ने इस दौरान विशेष एमटेक व पीजी कार्यक्रमों को शुरू करने पर अपनी मुहर लगाई। साथ ही संस्थानों में सिर्फ एकेडमिक प्रोफाइल बढ़ाने के लिए होने वाले पीएचडी प्रोग्राम को तुरंत बंद करने और उद्योगों की मांग आधारित व समस्या आधारित पीएचडी प्रोग्राम शुरू करने का भी निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रधान ने बताया कि काउंसिल में लिए गए फैसलों पर तुरंत काम शुरू हो जाएगा। साथ ही बदलाव भी अगले शैक्षणिक सत्र से दिखने लगेंगे।

धर्मेंद्र प्रधान। फाइल

काउंसिल के अन्य बड़े निर्णय

- परिषद ने नौकरी चाहने वालों को नौकरी देने वाला बनाने के लिए सभी संस्थानों को मजबूत इनोवेशन और रोजगार ईकोसिस्टम बनाने पर जोर दिया।
- सभी एनआइटी व आइआइएसईआर अपनी गुणवत्ता के लिए अनिवार्य रूप से नैक (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद) की रैंकिंग में हिस्सा लेंगे।
- सभी आइआइएसईआर में सेक्शन आठ के तहत एक कंपनी गठित होगी। जो रोजगार सृजन का काम करेगी।
- इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के लिए एनआइटी में जुलाई, 2026 में निवेशकों और उद्योगों की भागीदारी से एक पिंचिंग कान्क्लेव आयोजित होगा।
- अपने पाठ्यक्रमों व शोध को मांग के आधार पर भारतीय भाषाओं में शुरू करेंगे।

दिमाग को दुरुस्त रखने में जैविक घड़ी की अहम भूमिका

जनसत्ता ब्यूरो

अध्ययन

मानव शरीर में मौजूद 24 घंटे की जैविक घड़ी चुपचाप यह समन्वय करती है कि हम कब सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं और आराम करते हैं। यह आंतरिक समय प्रबंधन प्रणाली अंगों और हार्मोन को तालमेल बैठाकर काम करने में मदद करती है। हालांकि, जब जैविक घड़ी अव्यवस्थित हो जाती है, तो इसके प्रभाव खराब गुणवत्ता वाली नींद से कहीं अधिक व्यापक हो सकते हैं और ढलती उम्र में दिमागी सेहत में गिरावट का कारण भी बन सकते हैं। साल 2025 में 79 वर्ष की औसत आयु वाले दो हजार से अधिक बुजुर्गों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों की जैविक घड़ी अधिक व्यवस्थित होती है, उनके डिमेंशिया की चपेट में आने का जोखिम लगभग 50 फीसदी तक घट जाता है। रोजाना कम से कम 30 मिनट का व्यायाम, खासकर खुले वातावरण में और दोपहर से पहले, जैविक घड़ी को व्यवस्थित रखने और डिमेंशिया का जोखिम घटाने में मददगार साबित हो सकता है। पार्क में चहलकदमी और ध्यान लगाना दिमागी सेहत को दुरुस्त रखने के सबसे आसान और कारगर तरीकों में शामिल है।

क्यों अहम है जैविक घड़ी : जैविक घड़ी सोने का समय, हार्मोन का उत्पादन, हृदयगति और शरीर का तापमान सहित कई अन्य दैनिक शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाती है। अव्यवस्थित जैविक घड़ी को अक्सर नींद की खराब गुणवत्ता से जोड़ा जाता है। विभिन्न अध्ययनों में खराब गुणवत्ता वाली नींद का डिमेंशिया और दिल की बीमारियों के बढ़ते जोखिम से सीधा संबंध पाया गया है। साल 2025 में किए गए अध्ययन में प्रतिभागियों की दिल की सेहत और रक्तचाप का भी विश्लेषण किया गया, जो अन्य कारकों के साथ-साथ नींद की गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं।

जिन लोगों की जैविक घड़ी अधिक व्यवस्थित होती है, उनके डिमेंशिया की चपेट में आने का जोखिम लगभग 50 फीसदी तक घट जाता है। रोजाना 30 मिनट का सुबह व्यायाम और दोपहर से पहले, जैविक घड़ी को व्यवस्थित रखने और डिमेंशिया का जोखिम घटाने में मददगार साबित हो सकता है।

क्या है जैविक घड़ी : जैविक घड़ी (बायोलाजिकल क्लाक) शरीर की वह आंतरिक प्रणाली है जो नींद-जागने के चक्र, हार्मोन उत्पादन और चयापचय (मेटाबालिज्म) जैसी शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है, यह बाहरी रोशनी और अंधेरे के अनुसार लगभग 24 घंटे के चक्र में काम करती है, और इसे मस्तिष्क में मौजूद सुपरचियास्मैटिक न्यूक्लियस (एससीएन) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

शारीरिक निष्क्रियता घातक : नए अध्ययन से पता चलता है कि नींद में खलल से उपजने वाली थकान से पैदा शारीरिक निष्क्रियता को दूर करना ढलती उम्र में दिमाग को दुरुस्त रखने का कारगर तरीका हो सकता है। दरअसल, शारीरिक सक्रियता बढ़ाने से न सिर्फ वजन नियंत्रित रखने और मोटापा घटाने में मदद मिलती है, बल्कि नींद की गुणवत्ता में भी सुधार होता है और मस्तिष्क की कोशिकाओं में क्षरण की गति भी धीमी हो जाती है। अव्यवस्थित जैविक घड़ी और डिमेंशिया के बीच संबंधों के पीछे प्रतिरक्षा तंत्र का भी हाथ हो सकता है। विभिन्न अध्ययनों में देखा गया है कि व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता उसकी नींद की गुणवत्ता और जैविक घड़ी

भारत दो साल से भी कम समय में हुआ था पोलियोमुक्त

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत के जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में मंगलवार को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई। देश में पोलियो वायरस का आखिरी मामला सामने आए 15 साल पूरे हो गए। 2009 में भारत में पोलियो के 741 मामले थे, जो उस समय वैश्विक कुल मामलों का 60 प्रतिशत थे। हालांकि, संसाधनों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण देश में दो साल से भी कम समय में पोलियो का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। आखिरी मामला 2011 में सामने आया था।

इंटरनेशनल पीडियाट्रिक एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक डा. नवीन ठक्कर ने कहा कि भारत में पोलियो का आखिरी मामला दर्ज होने के 15 साल बाद, 'हमें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किए गए असाधारण प्रयासों की याद आती है। फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं ने हर समुदाय में विश्वास जगाया और देश ने इतने बड़े पैमाने पर टीके वितरित किए, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।"

शनि के चंद्रमा टाइटन पर उतरा यूरोपीय ह्यूजेंस अंतरिक्ष यान

2005 में आज ही यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के ह्यूजेंस प्रोब ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। यह बाहरी सौर मंडल में और पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह के चंद्रमा पर पहली लैंडिंग थी। इसके डाटा से टाइटन के कार्बनिक रसायन से युक्त सतह का पता चला।

Dainik Jagaran Page

BIHAR

सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा से ही बच्चे सीखेंगे एआइ

- केंद्र सरकार की गाइडलाइन को अमल करने में जुटा शिक्षा विभाग
- 31 हजार 297 विद्यालयों में होगी कंप्यूटर की व्यवस्था पहले चरण में

दीनानाथ साहनी, जागरण

पटना : नए शैक्षणिक सत्र से बिहार के सरकारी विद्यालयों में गुणात्मक सुधार के लिए कई बदलाव दिखेंगे। 71 हजार प्रारंभिक विद्यालयों की तीसरी कक्षा से ही बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की पढ़ाई होगी। शिक्षा मंत्रालय की नई गाइडलाइन के आधार पर शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को एआइ की पढ़ाई कराने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय ने 2026-27 सत्र से पूरे देश के विद्यालयों में एआइ पाठ्यक्रम को लागू करने की घोषणा की है। लिहाजा, शिक्षा विभाग पहले चरण में 31 हजार 297 मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर की व्यवस्था भी करने जा रही है। दूसरे चरण में 40,566 प्राथमिक विद्यालयों में भी कंप्यूटर की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि प्रारंभिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा समेत टेक्नोलाजी बेस्ड पढ़ाई सरकार की प्राथमिकता है।

शिक्षा विभाग के मुताबिक कंप्यूटर शिक्षा से जुड़े पाठ्यक्रम को राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार कराया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा भी टेक्नोलाजी बेस्ड कोर्स को उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें पाठ्य-पुस्तकें से लेकर हैंडबुक, वीडियो और डिजिटल सामग्री शामिल है। खास बात यह कि शिक्षा मंत्रालय आइआइटी, चेन्नई के विशेषज्ञों की टीम एआइ संबंधित पाठ सामग्री तैयार कर रही है। यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा, 2023 के आधार पर से तैयार किया जा रहा है।

निष्ठा से शिक्षकों को दिलाई जाएगी ट्रेनिंग

सरकारी विद्यालयों के बच्चों को एआइ की पढ़ाई कराने हेतु शिक्षकों की ट्रेनिंग निष्ठा (नेशनल इनिशिएटिव फार स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट) के माध्यम से दिलाई जाएगी। निष्ठा विद्यालय प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति हेतु राष्ट्रीय पहल है। यह केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए एक क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। शिक्षा विभाग के मुताबिक तीसरी कक्षा से बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कराई जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो बच्चे अभी एबीसीडी सीख रहे हैं, वे जल्द ही ये समझने लगेंगे कि रोबोट कैसे सोचता है। मशीनें कैसे बात करती हैं और टेक्नोलाजी से दुनिया को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इस संदर्भ में पहले शिक्षकों की एआइ पढ़ाने के बारे में ट्रेनिंग होगी।

प्रोजेक्ट का नाम एआइ एंड कंप्यूटेशनल थींकिंग

आसान भाषा में कहें तो यह पाठ्यक्रम बच्चों को टेक्नोलोजी की मदद से सोचना, समझना और समस्याओं का हल निकालना सिखाएगा। मसलन, अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि रोबोट को कैसे चलाएं तो वह सिर्फ बटन दबाना नहीं सीखेगा, बल्कि यह समझेगा कि रोबोट के अंदर क्या चल रहा है। शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक अगर बच्चे तीसरी कक्षा से एआइ सीख लें तो वे सिर्फ यूजर नहीं, बल्कि क्रिएटर बनेंगे।

Hindustan Page

सात निश्चय -3 का पर्यवेक्षक एवं अनुश्रवण बिहार विकास मिशन को

दरभंगा एयरपोर्ट के पास बनेगा लाजिस्टिक पार्क और कार्गो हब

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : राज्य सरकार दरभंगा हवाई अड्डे के पास लाजिस्टिक पार्क और कार्गो हब का निर्माण कराएगी। इसके लिए चिह्नित 50 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए अनुमानित 138.82 करोड़ रुपये मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 43 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि दरभंगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास लाजिस्टिक पार्क और कार्गो हब का निर्माण होने से मिथिला एवं उत्तर बिहार के कृषि और कृषि आधारित उत्पादों के एयर कार्गो परिवहन में वृद्धि होगी साथ ही आर्थिक विकास एवं समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। पांच वर्षों में बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के उद्देश्य से सात निश्चय तीन स्वीकृत किया है। मंत्रिमंडल ने मंगलवार को सात निश्चय -3 का पर्यवेक्षक एवं अनुश्रवण का दायित्व बिहार विकास मिशन को देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। मंत्रिमंडल ने पीएमश्री योजना के तहत 789 माध्यमिक विद्यालय व उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा के लिए 1485 करोड़ की योजना मंजूर की है। राशि से वर्ष 2025-26 के लिए चयनित 789 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कक्षा छह से लेकर 12वीं के विद्यार्थियों में आधुनिक शिक्षण, कौशल, नवाचार व तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।

50 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 138.82 करोड़ रुपये स्वीकृत

निर्बाध बिजली मिलेगी

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि. के क्षेत्राधीन गया इंटीग्रेटेड मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 220 केवी डीसी संचरण लाइन के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। यह लाइन चंदौती ग्रिड उपकेंद्र से आइएमसी, गयाजी तक होगी। इसके लिए 33.29 करोड़ रुपये की नई योजना स्वीकृत की गई है।

ऋण पर राजकीय गारंटी देने का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन मौसम 2025-26 और रबी विपणन मौसम 2026-27 में अधिप्राप्ति के लिए बिहार राज्य सहकारी बैंक को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नाबार्ड एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से कुल सात हजार करोड़ रुपये ऋण प्राप्त करने तथा ऋण के अंतर्गत जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों एवं उनके माध्यम से अधिप्राप्ति काम में लगी सहकारी संस्थाओं को दिए जाने वाले ऋण पर राजकीय गारंटी देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

वरिष्ठ विधायकों और मंत्रियों को मिलेगा अतिरिक्त आवास, चुकाना होगा मानक किराया

बिहार विधानमंडल के वरिष्ठ सदस्यों, मंत्रियों को सरकार ने पूर्व से आवंटित आवास के अतिरिक्त अन्य आवास देने का निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने भी स्वीकृति दे दी है। निर्णय के तहत वरिष्ठ विधायक, जो वर्तमान में मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं हैं, को विधानमंडल पूल में निर्वाचन क्षेत्रवार कर्णांकित आवास के अलावा पटना केंद्रीय पूल से कुल 15 आवास मिल सकेंगे। इसके लिए अतिरिक्त किराया देना होगा। अतिरिक्त आवास के लिए सरकार ने कुछ पात्रता और शर्तें भी निर्धारित की हैं। शर्तों के अनुसार ऐसे सदस्य इस सुविधा के हकदार होंगे, जो छह या उससे अधिक बार विधानमंडल के सदस्य चुने गए हों और कम-से-कम एक बार राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हों। या जिन्होंने कम-से-कम तीन बार राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्य किया हो या फिर पूर्व में मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हों।

अन्य निर्णय

- राज्य की 53 जेलों में 9073 सीसीटीवी कैमरा लगेंगे 155.38 करोड़ मंजूर।
- रोहतास सीमेंट (बंजारी सीमेंट) की क्षमता डेढ़ गुना करने का प्रस्ताव स्वीकृत। एक मिलियन की जगह 1.5 मिलियन टीपीडी क्षमता होगी।
- सुपौल के मझारी चौक से कनौली बाजार (नेपाल बार्डर) वाया डागमारा सड़क के 25.35 किलोमीटर के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए 126.24 करोड़ स्वीकृत।

चनपटिया स्टार्टअप की 58 वस्त्र इकाइयों को राहत, निवेश में ढील

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : सरकार ने चनपटिया स्टार्टअप जोन परिसर में संचालित टेक्सटाइल एवं वस्त्र उद्योग से जुड़ी इकाइयों को बड़ी राहत दी है। मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग द्वारा पूर्व में जारी संकल्प में संशोधन करते हुए विशेष परिस्थिति के तहत इस स्टार्ट-अप को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इसके अंतर्गत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति में आवश्यक संशोधन किया गया है। संशोधित प्रविधान के तहत चनपटिया स्टार्टअप जोन परिसर में स्थित 58 इकाइयों के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन के लिए निर्धारित न्यूनतम निवेश सीमा 25 लाख रुपये की शर्त को शिथिल किया गया है। इससे छोटी और नवोदित इकाइयों को भी सरकारी प्रोत्साहन का लाभ मिल सकेगा। साथ ही बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड (बीआइसीआइसीओ) के माध्यम से इन इकाइयों को नौ प्रतिशत वार्षिक रियायती ब्याज दर पर तीन वर्षों के लिए अल्पावधि ऋण (शार्ट टर्म लोन) उपलब्ध कराया जाएगा।

शोध | एनआईटी पटना समेत कई संस्थानों के विशेषज्ञों ने अध्ययन से निकाला निष्कर्ष, राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन वेटलैंड एंड वाटर रिसोर्स बनाने का दिया प्रस्ताव

तालाब और आर्द्रभूमि बढ़ाने से नदियों का गाद संकट दूर होगा

हि विशेष

■ संजय पांडेय

पटना। तालाबों, आर्द्रभूमि, आहर-पइन की संख्या बढ़ाने से सूबे की नदियों का गाद संकट से बचाव होगा। साथ ही बाढ़ की विभिषिका और उपजाऊ भूमि के क्षरण से भी मुक्ति मिलेगी। नदियों की जलधारा क्षमता बढ़ेगी। कटाव कम होगा और जैव-विविधिता में भी सुधार होगा। एनआईटी पटना समेत देश के शीर्ष इंजीनियरिंग व शोध संस्थानों के विशेषज्ञों के शोध और अध्ययन में ये बातें कही गईं।

शोध के आधार पर विशेषज्ञों ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। इसको सरकार को भेजा जाएगा। प्रस्ताव में विशेषज्ञों ने राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन वेटलैंड एंड वाटर रिसोर्सेस खोलने के सुझाव दिए हैं। कहा गया है कि इस सेंटर के खुलने से नदियों के बहाव, बहाव में परिवर्तन, बाढ़ की विभिषिका, विलुप्त तालाबों का दुष्प्रभाव, राज्य की विलुप्त होती आर्द्रभूमि और तालाबों और आर्द्रभूमि के फायदे आदि विषयों के साथ ही जैव-विविधता का भी अध्ययन होगा।

जहां संरक्षण वहां भू-जलस्तर अब भी अनुकूल: प्रस्ताव से पहले विशेषज्ञों की टीम द्वारा बक्सर के गोकुल जलाशय, बेगूसराय के कांवड़ ताल और दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में स्थित तालाबों का भी अध्ययन किया गया। ये तीनों संयुक्त राष्ट्र के रामसर संरक्षित जलाशय की श्रेणी में हैं। अध्ययन में पाया गया कि इन जलाशयों के कारण आसपास में बाढ़ का प्रकोप कम है, पर्याप्त जैव विविधता के मामले में भी ये इलाका संपन्न है। दूसरी ओर खेतों की ऊपरी परत पर स्थित उपजाऊ मिट्टी भी बहकर नदियों में जा रही है। जल प्रदूषण से नदियों के फ्लोरा और फाउना जैसे सूक्ष्म जीवों की संख्या घटी। नदी और इसके किनारे के जैव-विविधता पर प्रतिकूल असर पड़ा।

■ देश-दुनिया के 100 विशेषज्ञों के सुझाव पर बना प्रस्ताव

कैसे प्रस्ताव तैयार हुआ, क्या है विशेषज्ञों का अध्ययन

डॉ. रमाकार झा ने बताया कि दिसंबर में एनआईटी पटना की ओर से एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार वेट-वार 2025 हुआ था। इसमें देश-विदेश के 100 से ज्यादा विशेषज्ञ-वैज्ञानिक शामिल हुए। सभी ने बिहार के जलीय क्षेत्र, ऊपजाऊ भूमि और जैव-विविधता को बचाने के लिए शोध के आधार पर प्रस्ताव तैयार किए। विशेषज्ञों में डॉ. रमाकार झा, एनआईटी पटना के निदेशक प्रो. पीके जैन, टेक्सास विवि. अमेरिका के प्रो. विजय प्रसाद सिंह, आईआईटी धारवाड़ के निदेशक प्रो. वीआर देसाई, एनआईटी वारंगल के निदेशक प्रो. बी सुबुद्धित शामिल थे। विशेषज्ञों के बीच बिहार में मौजूद जल संसाधन, पूर्व और वर्तमान में नदियों, तालाबों की स्थिति, बाढ़ की विभिषिका और इससे बचाव के उपायों पर चर्चा हुई। सभी इस विषय पर एकमत हुए कि अतिक्रमण से राज्य में आर्द्रभूमि, तालाबों की संख्या में काफी कमी आई है।

तालाब में वर्षा जल संरक्षित कर भूजलस्तर बढ़ाएंगे

प्रस्ताव में आर्द्रभूमि और तालाबों की संख्या और क्षेत्रफल बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। नदियों के पहले तालाबों के रहने से वर्षा जल का संरक्षण होगा। इससे भू-जल बढ़ेगा। बारिश के दिनों में नदियों में सीधे गाद और गंदगी नहीं जाएगी। जलीय जीवों, पक्षियों का आना शुरू होगा। हरियाली बढ़ेगी। प्रदूषण कम होगा। जल पर्यावरण के अनुकूल फ्लोरा और फौना जैसे सूक्ष्म जलीय जीवों की संख्या भी बढ़ेगी। नदी से पहले तालाब आदि पर्याप्त संख्या में होंगे तो नदियों में गाद कम जमा होगी, जलधारण की क्षमता बढ़ेगी और बाढ़ की विभिषिका में भी कमी आ सकती है।

सोन नद जल बंटवारे पर बिहार-झारखंड सहमत

लंबे समय से अटकी इंद्रपुरी परियोजना का रास्ता साफ

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : बिहार-झारखंड के बीच बीते 26 वर्षों से जिस पानी के बंटवारे को लेकर विवाद था आखिरकर उसका समाधान हो गया। इस जल बंटवारे के साथ ही बिहार में लंबे समय से अटकी इंद्रपुरी जलाशय परियोजना को नई दिशा मिल गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार-झारखंड के बीच 7.75 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) जल बंटवारे के एकरारनामा के प्रारूप को स्वीकृति दे दी गई। आज की बैठक में कुल 43 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

राज्य बंटने के बाद झारखंड ने मांगा अपना हिस्सा : मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि वर्ष 1973 में हुए वाणसागर समझौते के तहत अविभाजित बिहार को सोन नद से 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल का आवंटन हुआ था। वर्ष 2000 में राज्य विभाजन के बाद झारखंड ने इस जल पर अपने हिस्से की मांग रखी, जिससे इंद्रपुरी जलाशय परियोजना वर्षों तक उलझी रही। विभिन्न स्तर पर प्रयासों के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं निकल रहा था।

मुंबई में बनेगा बिहार भवन, 314 करोड़ स्वीकृत : राज्य मंत्रिमंडल ने मुंबई में बिहार भवन निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इसके साथ ही भवन निर्माण के लिए 314.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी है।

कैबिनेट के निर्णय

5.75 बिहार को तो झारखंड को 2.00 मिलियन एकड़ फीट जल मिलेगा

इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण जरूरी

लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान दैनिक जागरण के घोषणा पत्र में इंद्रपुरी जलाशय परियोजना को पुरजोर तरीके से शामिल किया गया था।

क्षेत्रीय परिषद की बैठक में दोनों राज्य हुए थे सहमत

चौधरी ने बताया कि 10 जुलाई 2025 को रांची में हुई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में दोनों राज्यों के बीच सहमति बनी कि 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल में से 5.75 मिलियन एकड़ फीट बिहार और दो मिलियन एकड़ फीट जल झारखंड को मिलेगा। इस सहमति के साथ ही रोहतास से लगभग 80 किलोमीटर दूर अगियांव में प्रस्तावित इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण की सबसे बड़ी बाधा समाप्त हो गई है। अब परियोजना की डीपीआर तैयार करने का कार्य शुरू होगा। जलाशय के निर्माण से भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, पटना, गया और अरवल जिलों के किसानों को सिंचाई की स्थाई सुविधा मिलेगी। जिससे कृषि उत्पादन को नया बल मिलेगा।

कैबिनेट के निर्णय से गयाजी का विकास होगा

डा. प्रेम कुमार

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : विधानसभा अध्यक्ष डा. प्रेम कुमार ने गयाजी परियोजना को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के लिए 220 केवी डीसी ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण की नई योजना की स्वीकृति पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से गयाजी में विकास की गति तेज होगी। डा. प्रेम कुमार ने मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उनके बीच संसदीय परंपराओं एवं संवैधानिक मूल्यों पर चर्चा हुई।

कैबिनेट : छठी से 12वीं तक के छात्रों को आधुनिक शिक्षा-नवाचार और तकनीक में दक्ष बनाने का लक्ष्य

राज्य के 789 स्कूलों में स्मार्ट क्लास, लैब बनेंगी

1485 करोड़ इस पर खर्च होंगे

फैसला 1

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य के 789 माध्यमिक विद्यालय व उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में आधुनिक शिक्षण की व्यवस्था होगी। इन स्कूलों के छठी से 12वीं तक के छात्रों को आधुनिक शिक्षा, कौशल नवाचार, तकनीकी साक्षर बनाने की योजना है।

इसके तहत चयनित विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, लैब और लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गयी। बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।

बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि इसके लिए 1485.85 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। इस राशि से वर्ष 2025-26 के लिए चयनित 789 विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कक्षा छह से 12वीं तक के विद्यार्थियों में आधुनिक शिक्षण, कौशल, नवाचार व तकनीकी साक्षरता को बढ़ावा दिया जाएगा।

गुणवत्तापूर्ण एवं कौशल आधारित शिक्षा : विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं कौशल आधारित शिक्षा मिलेगी। साथ ही उक्त विद्यालयों के शिक्षकों को आधुनिक प्रशिक्षण देकर बेहतर शिक्षण प्रणाली विकसित की जाएगी। ❯अन्य फैसले P 4,10

43 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में

■ चयनित विद्यालयों में आधुनिक पुस्तकालय की स्थापना भी की जाएगी

इंद्रपुरी जलाशय निर्माण के लिए झारखंड से करार को हरी झंडी

फैसला 2

■ समझौते के बाद इसके लिए डीपीआर निर्माण पर काम प्रारंभ होगा

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार में इन्द्रपुरी जलाशय निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सोन नद के जल बंटवारे पर बिहार और झारखंड के सहमत होने के बाद दोनों राज्यों के बीच एमओयू के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिपरिषद ने सहमति दे दी।

इस तरह रोहतास से 80 किलोमीटर दूर अगियांव में इन्द्रपुरा जलाशय निर्माण की बड़ी बाधा दूर हो गयी है। बिहार-झारखंड के बीच समझौते के बाद इसके लिए डीपीआर निर्माण पर काम प्रारंभ होगा। जलाशय के निर्माण से भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, पटना, गया के अलावा अरवल जिले में किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी। 1973 में हुए वाणसागर समझौते के अनुसार अविभाजित बिहार को 7.75 मिलियन एकड़ फुट जल आवंटित हुआ था। वर्ष 2000 में राज्य के बंटवारे के बाद झारखंड ने बिहार कोटे के पानी में अपनी हिस्सेदारी मांगी। इस वजह से बिहार की इंद्रपुरी जलाशय परियोजना पर सहमति नहीं हो पा रही थी।

वन पर्यावरण सलाहकार समेत 1161 पदों पर बहाली होगी

फैसला 3

■ कृषि विभाग में कुल 694 पदों के पुनर्गठन एवं सृजन को स्वीकृति

पटना। विभिन्न विभागों में 1161 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत कृषि विभाग के अधीन स्वीकृत 293 पदों के समर्पण एवं प्रत्यर्पण के बाद 194 पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक तथा 99 पौधा संरक्षण निरीक्षक सहित 694 पदों के पुनर्गठन एवं सृजन को स्वीकृति मिली है। वहीं, वन एवं पर्यावरण विषयों के समाधान के लिए एक पद वन एवं पर्यावरण सलाहकार का सृजन हुआ है।

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के कार्यालय परिचाली संवर्ग के 200 पदों के चिह्नितीकरण एवं पुनर्गठन को मंजूरी दी गयी। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के लिए 147 पद, राजकीय पॉलिटेक्निक, बगहा में सत्र 2026-27 से पठन-पाठन को लेकर 106, जन शिक्षा निदेशालय के लिए नौ पद और पटना हाइकोर्ट में अतिरिक्त विधि सहायकों के चार पदों के सृजन की स्वीकृति भी मिली है। पूर्व में सृजित विधि लिपिक का पदनाम भी विधि सहायक किया गया है।

फैसला 4

विधानमंडल का सत्र दो फरवरी से, तीन को बजट पेश होगा

बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होगा। यह 27 फरवरी तक चलेगा। तीन फरवरी को बजट पेश होगा। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव पर भी सहमति प्रदान की गई।

फैसला 5

मुम्बई में बनेगा बिहार भवन

राज्य मंत्रिपरिषद ने मुंबई में बिहार भवन निर्माण को मंजूरी प्रदान की। इसके निर्माण के लिए 314.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की। इन फैसलों को राज्य के विकास, प्रशासनिक सुगमता और जनहित की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। वहीं खरीफ विपणन मौसम 2025-26 और रबी विपणन मौसम 2026-27 में अधिप्राप्ति कार्य के लिए राज्य सहकारी बैंक को नाबार्ड एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से 7000 करोड़ लेने तथा इस ऋण के अंतर्गत सहकारी बैंक-संस्थाओं को दिए जाने वाले राजकीय गारंटी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

देशभर का 12.30% शहद का उत्पादन बिहार में : मंत्री

पटना. कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि राज्य में मधु उत्पादन में 177 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय मधु उत्पादन में बिहार का योगदान 12.30 प्रतिशत रहा. वर्तमान में राज्य का मधु उत्पादन लगभग 18,600 मीट्रिक टन है. वर्ष 2025-26 के लिए 22,000 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. कृषि मंत्री ने कहा कि इस उपलब्धि को और गति देने के लिए राज्य सरकार शहद नीति लाने जा रही है. मधु उत्पादन, प्रसंस्करण, गुणवत्ता, ब्रांडिंग और मार्केटिंग व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है. बिहार के शहद को देश-विदेश के बाजारों में बेहतर पहचान है.

Hindustan Page

Dainik Jagran Page

खतरनाक: आईआईटी बीएचयू ने पटना में अध्ययन किया, प्रारंभिक रिपोर्ट में बात आयी सामने

नालों से निकल रही अमोनिया गैस सल्फर संग महीन धूलकण बना रही

■ नीरज कमल

पटना। पटना के खुले नाले भी वायु प्रदूषण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खुले नाले से अमोनिया गैस निकल रही है। यह वाहनों से निकलने वाले सल्फर डाईऑक्साइड (एसओ2) से मिलकर पीएम 2.5 यानी महीन धूलकण बन रही है। दोनों गैस के आपस में मिलने से महीन कण बन रहे हैं। इसके कारण पीएम2.5 की मात्रा लगातार बढ़ी हुई पायी जा रही है।

इसका खुलासा आईआईटी बीएचयू के एक अध्ययन में हुआ है। पटना के वायु प्रदूषण में कमी जरूर आयी है, पर पीएम2.5 अक्सर बढ़ा हुआ रहता है। ऐसी ही स्थिति सूबे के अन्य छोटे शहरों की भी है। मालूम हो कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद का आईआईटी बीएचयू को पटना में वायु प्रदूषण के कारणों का पता लगाने के लिए अध्ययन करने को लेकर समझौता हुआ था। अध्ययन के लिए एक साल का समय निर्धारित था, जो अब पूरा हो चुका है। हालांकि अंतिम रिपोर्ट आने में अभी दो माह का समय और लगेगा। आईआईटी बीएचयू की टीम ने पटना के खुले नाले का सैंपल लेकर उसकी जांच की थी। अभी प्रारंभिक रिपोर्ट में यह साबित हो चुका है कि खुले नाले से निकलने वाली अमोनिया गैस के कारण भी वायु में पीएम2.5 की मात्रा बढ़ रही है।

खुले नालों को बंद करना होगा : बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष डॉ. डीके शुक्ला ने बताया कि अध्ययन की प्रारंभिक रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है कि खुले नाले से निकल रही अमोनिया गैस से भी पीएम 2.5 बढ़ रहा है। अभी अंतिम रिपोर्ट आनी बाकी है। शहर के खुले नालों को बंद करने से ही पीएम2.5 में कमी आएगी। हालांकि कई नालों को बंद किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद कार्ययोजना बनाकर सरकार को बताएंगे। खुले नाले में आर्गेनिक मेटेरियल होते हैं। गंदगी और कचरा होता है। इसके कारण अमोनिया गैस निकलती है। शहर के वायु में पहले से ही वाहनों से निकलने वाले सल्फर डाईऑक्साइड मौजूद रहता है। दोनों के मिलने से भी पीएम 2.5 बन रहा है। धूप निकलने पर अमोनिया हवा में प्रवेश कर जाता है। इससे ऐसी स्थिति बन रही है।

■ बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को मार्च तक बीएचयू आईआईटी से अंतिम रिपोर्ट मिलेगी

वायु गुणवत्ता सूचकांक

शहर	सूचकांक
बेतिया	184
बेगूसराय	162
पटना	144
मोतिहारी	127
कटिहार	128
हाजीपुर	125
बिहारशरीफ	119
बक्सर	113
आरा	71

सूबे के 10 शहरों में पीएम 2.5 ने बढ़ाया वायु प्रदूषण

सूबे के छोटे शहरों में ज्यादातर पीएम2.5 की मात्रा बढ़ी हुई रहती है। मंगलवार को जिन शहरों में पीएम2.5 बढ़ा हुआ पाया गया, उनमें आरा, हाजीपुर, कटिहार, मोतिहारी, पटना, अररिया, बेगूसराय, बेतिया, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर और बक्सर शामिल है। सुबह में आरा और हाजीपुर का राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से अधिक था। हालांकि शाम होते होते आरा का सूचकांका 71 और हाजीपुर 125 तक पहुंचा है। पीएम 2.5 स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक खतरनाक है। यह सबसे महीन कण होता है, जो सांस के जरिए फेफड़े तक पहुंचता है।

पंचायतों की जैव विविधता प्रबंधन समितियों को नए सिरे से किया जा रहा सक्रिय

राज्य की पंचायतों का अब होगा जैव विविधता आधारित विकास

हि विशेष

■ मनीष कुमार भारतीय

गोपालगंज। बिहार के सभी 38 जिलों की 8 हजार 53 पंचायतों में अब स्थानीय जैव विविधता के संवर्द्धन को केंद्र में रखकर विकास योजनाएं तैयार की जाएगी। इसके लिए बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद की ओर से ठोस पहल शुरू की गई है। हाल के वर्षों में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन और इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए पंचायतों में गठित जैव विविधता प्रबंधन समितियों को नए सिरे से सक्रिय किया जा रहा है।

इस उद्देश्य से जिला और अनुमंडल स्तर पर लगातार कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें पंचायत प्रतिनिधियों और जैव विविधता प्रबंधन समिति के सदस्यों को जैव विविधता के दृष्टिकोण से विकास योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इस अभियान में पंचायती राज, वन, कृषि, पशुपालन, उद्यान, मत्स्य संसाधन सहित अन्य संबंधित विभागों का सहयोग लिया जा रहा है।

पंचायतों में तैयार हो रही जैव विविधता पंजी: राज्य की प्रत्येक पंचायत में जैव विविधता पंजी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पंजी में स्थानीय जैव संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान, प्राकृतिक धरोहरों, औषधीय पौधों और स्थानीय प्रजातियों का विवरण दर्ज किया जाएगा। इससे पंचायत स्तर पर पारंपरिक मोटे अनाज की खेती, फसल चक्र अपनाने, पशुपालन को बढ़ावा देने, जल स्रोतों के संरक्षण तथा स्थानीय पशु-पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाएं बनाने में सहायता मिलेगी।

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के अनुसार इस पहल से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा, बल्कि ग्रामीण आजीविका का विकास होगा और सतत विकास को भी मजबूती मिलेगी।

37 जिला में हो चुकी हैं कार्यशालाएं: नालंदा, नवादा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, जमुई, सहरसा, भोजपुर, सीतामढ़ी, शिवहर सहित अब तक 37 जिला और अनुमंडल मुख्यालयों में राज्य जैव विविधता पर्षद की ओर से पंचायत प्रतिनिधियों, जैव विविधता प्रबंधन समितियों और विभागीय पदाधिकारियों के साथ कार्यशाला आयोजित की जा चुकी हैं। इन बैठकों में पंचायत की आम सभा में जैव विविधता संवर्द्धन आधारित योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। गोपालगंज, सारण और सीवान जिलों में अगले माह बैठकें प्रस्तावित हैं।

08 हजार 53 कुल पंचायतें हैं बिहार में, 10 हजार रुपए की राशि हर पंचायत को भेजी गई

इस तरह तैयार होंगी विकास योजनाएं

- जलवायु के लिहाज से पारंपरिक मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा मिलेगा
- फसल चक्र, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को योजनाओं में शामिल किया जाएगा
- देसी नस्लों के पशुओं के संरक्षण को भी योजनाओं में प्रमुखता दी जाएगी
- जल स्रोतों के पुनर्जीवन संरक्षण को योजनाओं में शामिल किया जाएगा

"बिहार में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य जैव विविधता पर्षद ने पंचायत स्तर पर जैव विविधता आधारित विकास योजनाएं बनाने की पहल शुरू की है। मुखिया की अध्यक्षता वाली जैव विविधता प्रबंधन समितियों को सक्रिय कर प्रत्येक को 10 हजार रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।"
– हेमकांत राय, संयुक्त निदेशक, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद

बिहार में शहद क्रांति लाने के लिए आएगी नई नीति

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई नीति लाएगी। इससे शहद उत्पादन, प्रसंस्करण, गुणवत्ता, ब्रांडिंग और मार्केटिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में मदद मिलेगी। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि राज्य ने मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति दर्ज की है। बिहार में शहद उत्पादन देश का 12.30 फीसदी है। राज्य का मधु उत्पादन लगभग 18,600 मीट्रिक टन है। वर्ष 2025-26 के लिए 22,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य है। पिछले एक दशक में शहद उत्पादन में 177 फीसदी की वृद्धि हुई है। अब बिहार के शहद उत्पादकों को उचित मूल्य और पहचान दिलाने की दिशा में कार्य शुरू किया गया है।

उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन योजना के जरिए छोटे सीमान्त, भूमिहीन परिवारों, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को कम लागत, कम जगह और कम समय में रोजगार एवं अतिरिक्त आय मिलेगी। योजना के तहत मधुमक्खी कॉलोनी, छत्ता/बॉक्स, शहद निष्कर्षण उपकरण (हनी इक्सट्रैक्टर) व फूड-ग्रेड कंटेनर (जो स्वच्छ निष्कर्षण, सुरक्षित भंडारण व गुणवत्ता संरक्षण में सहायक होगा) सहित आवश्यक उपकरणों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण युवाओं से योजना का लाभ उठाने की अपील की।

■ कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, बिहार में देश का 12.30% शहद का उत्पादन
■ उत्पादन, प्रसंस्करण, गुणवत्ता, ब्रांडिंग और मार्केटिंग व्यवस्था सुदृढ़ होगी

NATIONAL

देश में प्रतियोगिताओं की मेजबानी जैसे मुद्दे पर | निर्देश | विश्व संस्थानों के साथ बेहतर सहयोग बनाने की कवायद

खेल मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय संबंध समिति गठित करने को कहा

नई दिल्ली, 13 जनवरी (भाषा)।

खेल मंत्रालय ने संयुक्त अभ्यास कार्यक्रमों और भारत में प्रमुख प्रतियोगिताओं की मेजबानी जैसे मुद्दों पर विश्व संस्थाओं के साथ बेहतर सहयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) से अंतरराष्ट्रीय संबंध समिति गठित करने को कहा है। मंत्रालय ने इसके साथ ही एनएसएफ से भारतीय निर्माताओं, स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थानों और परीक्षण एवं मानकीकरण निकायों के साथ जुड़ने के लिए 'मेक इन इंडिया खेल समिति' का गठन करने को भी कहा है ताकि खेल विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया जा सके।

एनएसएफ को भेजे गए अपने पत्र में मंत्रालय ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंध समिति में महासंघ के वरिष्ठ सदस्य, पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, कोच और 'वैश्विक खेल प्रशासन और कूटनीति का अच्छा अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ' शामिल होने चाहिए।

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
DEPARTMENT OF SPORTS

एनएसएफ को भेजे गए अपने पत्र में मंत्रालय ने कहा कि समिति के संपूर्ण विवरण के बारे में 30 दिनों के अंदर मंत्रालय को सूचित कर दिया जाए। मंत्रालय की यह सलाह खेल सचिव हरि रंजन राव द्वारा एनएसएफ के अधिकारियों से दैनिक प्रशासन का काम सीईओ पर छोड़ने और भारत के फायदे के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करने के कुछ दिनों बाद आई है।

मंत्रालय ने कहा, 'समिति के संपूर्ण विवरण के बारे में 30 दिनों के अंदर मंत्रालय को सूचित कर दिया जाए।' मंत्रालय की यह सलाह खेल सचिव हरि रंजन राव द्वारा एनएसएफ के अधिकारियों से दैनिक प्रशासन का काम सीईओ पर छोड़ने और भारत के फायदे के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करने के कुछ दिनों बाद आई है। उन्होंने पिछले सप्ताह अहमदाबाद में कहा था, 'आप दूरदृष्टा निर्माता हैं, प्रशासक नहीं। आपको अपने संगठन में पेशेवर प्रशासकों की जरूरत है जो महासंघ के दैनिक कार्यों को संभाल सकें। आप अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ संबंध विकसित करने और विकास की योजनाएं तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करें।'

मंत्रालय की सलाहकार समिति ने कहा कि इस तरह की समिति के गठन की सलाह देने का निर्णय 'तेजी से बदलते वैश्विक खेल परिवेश' को ध्यान में रखते हुए दी गई। 'मेक इन इंडिया' समिति में महासंघ के वरिष्ठ सदस्य, तकनीकी विशेषज्ञ, पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और खेल उपकरण या प्रौद्योगिकी, विनिर्माण या मानकों में अनुभव रखने वाला कम से कम एक सदस्य शामिल होना चाहिए।

3.25 लाख करोड़ के 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी

- इन लड़ाकू विमानों का निर्माण भारत में करीब 30 फीसद स्वदेशी सामग्री के साथ किया जाएगा
- अगले दो-तीन दिनों में रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा के लिए रखे जाएंगे प्रस्ताव

नई दिल्ली, एएनआइः एक अहम घटनाक्रम में भारत इस हफ्ते रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में फ्रांस से करीब 3.25 लाख करोड़ रुपये के 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे पर चर्चा करने जा रहा है। इनका निर्माण भारत में ही करीब 30 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री के साथ किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि भारत, फ्रांस के साथ इस समझौते को ऐसे समय में आगे बढ़ा रहा है जब अमेरिका व रूस दोनों ने भारतीय वायु सेना को पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, जिनमें क्रमशः एफ-35 और एसयू-57 शामिल हैं, देने की पेशकश की है।

अगले दो-तीन दिनों में होने वाली रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा के लिए रखे जाने वाले प्रस्ताव के अनुसार, इस सौदे में वायु सेना द्वारा करीब 12-18 राफेल जेट विमानों को अधिग्रहित करना भी शामिल होगा। भारतीय पक्ष फ्रांस से यह भी अनुरोध कर रहा है कि वह सरकार-से-सरकार समझौते के तहत भारतीय हथियारों व अन्य स्वदेशी प्रणालियों को फ्रांसीसी विमानों में एकीकृत करने की अनुमति दे। सोर्स कोड केवल फ्रांसीसी पक्ष के पास ही रहेंगे।

राफेल विमानों में स्वदेशी घटक सिर्फ 30 प्रतिशत के आसपास होंगे। आम तौर पर, मेक इन इंडिया परियोजनाओं में स्वदेशी घटक की जरूरत 50-60 प्रतिशत होती है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होगा। इससे भारतीय सेना में राफेल की संख्या 176 हो जाएगी। वायु सेना के पास पहले से ही 36 जेट हैं, जबकि नौसेना ने पिछले साल 26 जेट का आर्डर दिया था। "भारतीय वायु सेना द्वारा तैयार किए गए 114 राफेल जेट के प्रस्ताव का विवरण रक्षा मंत्रालय को कुछ महीने पहले प्राप्त हुआ था। रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद, इस प्रस्ताव को कैबिनेट कमेटी आन सिक्योरिटी से अंतिम मंजूरी लेनी होगी।"

गौरतलब है कि इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का कदम आपरेशन सिंदूर में राफेल के शानदार प्रदर्शन के तुरंत बाद उठाया गया, जहां इसने अपने 'स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रानिक वारफेयर सूट' का उपयोग करके चीनी पीएल-15 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था।

भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम की धारा 17ए पर सुप्रीम कोर्ट का खंडित फैसला

रद्द हो : न्यायमूर्ति नागरत्ना, वैध : न्यायमूर्ति विश्वनाथन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 13 जनवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच शुरू करने से पहले अनुमति लेने से संबंधित, भ्रष्टाचार रोधी कानून की 2018 की धारा की संवैधानिक वैधता पर मंगलवार को खंडित निर्णय सुनाया।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए असंवैधानिक है और इसे रद्द किया जाना चाहिए जबकि न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने धारा को संवैधानिक मानते हुए ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा की जरूरत पर जोर दिया।

साल 2018 में जोड़ी गई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के तहत सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना किसी लोकसेवक पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) 'सेंटर फार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' (सीपीआइएल) की जनहित याचिका (पीआइएल) पर यह निर्णय सुनाया है, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संशोधित धारा 17ए की वैधता को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि पूर्वानुमति की आवश्यकता भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विरुद्ध है, इससे जांच में रुकावट आती है और भ्रष्ट अधिकारियों को बचने का मौका मिल जाता है।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच शुरू करने से पहले पूर्वानुमति की आवश्यकता भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विरुद्ध है। इससे जांच में रुकावट आती है और भ्रष्ट अधिकारियों को बचने का मौका मिल जाता है।

न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा, 'धारा 17ए संवैधानिक रूप से वैध है, बशर्ते मंजूरी देने का फैसला लोकपाल या राज्य का लोकायुक्त करे। इस प्रावधान से ईमानदार अधिकारियों की रक्षा होगी और भ्रष्ट लोगों के लिए सजा सुनिश्चित होगी।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने कहा, 'धारा 17ए असंवैधानिक है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। जांच शुरू करने से पहले किसी तरह की पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। पूर्व मंजूरी की शर्त अधिनियम के उद्देश्य के खिलाफ है। इससे जांच में रुकावट आ सकती है और ईमानदार अधिकारियों के बजाय भ्रष्ट लोकसेवकों को संरक्षण मिलता है।'

न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा, 'धारा 17ए संवैधानिक रूप से वैध है, बशर्ते मंजूरी देने का फैसला लोकपाल या राज्य का लोकायुक्त करे। इस प्रावधान से ईमानदार अधिकारियों की रक्षा होगी और भ्रष्ट लोगों के लिए सजा सुनिश्चित होगी। इससे प्रशासनिक व्यवस्था में देश की सेवा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।'

अब यह मामला भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष रखा जाएगा, ताकि एक बड़ी पीठ का गठन कर इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सके। पीठ ने कहा, 'हमारे अलग-अलग मतों को देखते हुए रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि इस मामले को प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए, ताकि उपयुक्त पीठ का गठन करके इससे जुड़े मुद्दों पर नए सिरे से बाकी पेज 10 पर

सेना प्रमुख बोले- युद्ध में रॉकेट, मिसाइलों और ड्रोन का बढ़ता इस्तेमाल चिंताजनक

देश को रॉकेट फोर्स की जरूरत

तैयारी

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा कि भारत को अब रॉकेट-मिसाइल फोर्स की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश को ऐसी फोर्स चाहिए, जिसमें रॉकेट और मिसाइल दोनों की क्षमताएं मौजूद हों। चीन और पाकिस्तान पहले ही इस तरह की फोर्स खड़ी कर चुके हैं।

सेना दिवस से पूर्व वार्षिक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने बताया कि भारत पिनाका रॉकेट सिस्टम को लगातार मजबूत कर रहा है। इसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक है। इसके अलावा, प्रलय सहित अन्य रॉकेट और मिसाइल प्रणालियों पर भी काम चल रहा है। मौजूदा हालात में रॉकेट और मिसाइल फोर्स भारत की जरूरत बन चुकी है तथा सरकार भी इस पर सहमत है। अब फैसला यह होना है कि यह फोर्स सेना के भीतर रहेगी या रक्षा मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में होगी।

सेना प्रमुख ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने अपनी तैयारियों में कई अहम बदलाव किए हैं। हाल ही में सेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप (आईबीजी) के गठन को मंजूरी दी गई है। मेजर जनरल स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में सेना की 16 यूनिटों को मिलाकर ऐसे समूह बनाए जाएंगे, जिनके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

नई दिल्ली में मंगलवार को पत्रकार वार्ता के दौरान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी।

जनरल द्विवेदी ने बताया कि भविष्य की युद्ध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भैरव, शक्तिमान, दिव्यास्त्र और रुद्र ब्रिगेड जैसी इकाइयों के गठन की प्रक्रिया भी चल रही है। ट्रेनिंग कमांड का विस्तार किया जा रहा है, ताकि सेना आने वाली चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सके। सेना प्रमुख ने कहा कि युद्धक तैयारियों को मजबूत करने के लिए तैनाती व्यवस्था में भी नए सिरे से बदलाव किए जा रहे हैं।

ड्रोन से जुड़ी चुनौतियों पर जनरल द्विवेदी ने कहा, सेना एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रही है। ड्रोन की पहचान के लिए छोटे और आधुनिक रडार लगाए जा रहे हैं। वर्तमान में पाक सीमा पर करीब 10 हजार ड्रोन सक्रिय हैं। सेना में टेक्नो-कमांडर तैयार किए जा रहे हैं। सेना प्रमुख ने यह भी कहा, आज सेना को मजबूत महिला अफसरों की जरूरत है, जो काली माता के रूप का प्रतीक हों। इस सवाल पर कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक सेना ने परमाणु हमले की धमकी दी थी, सेना प्रमुख ने कहा कि डीजीएमओ स्तर पर ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठा।

पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को हथियार देने से जुड़े सवाल पर सेना प्रमुख ने कहा, ये फैसले स्थायी सरकार के नहीं लगते। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच संवाद जारी है और बांग्लादेश की सेना भारत के खिलाफ नहीं है। क्षमता विकास के मामले में वे फैसले ले सकते हैं, लेकिन भारत नजर रखे हुए है। सेना प्रमुख ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में आठ आतंकी शिविर फिर से सक्रिय हो गए हैं। इनमें से छह शिविर नियंत्रण रेखा के पार और दो अंतरराष्ट्रीय सीमा के उस पार संचालित हो रहे हैं। भारतीय सेना गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे है।

36 आतंकी मारे गए घाटी में बीते वर्ष, इनमें 65 फीसदी पाकिस्तानी

शक्सगाम घाटी पर चीन का दावा खारिज किया

शक्सगाम घाटी को लेकर चीन के दावों पर सेना प्रमुख ने कहा, विदेश मंत्रालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि भारत, चीन और पाक में हुई संधि स्वीकार नहीं करता। पाक ने वर्ष 1963 में अवैध रूप से कब्जाए भारतीय क्षेत्र में से शक्सगाम घाटी का 5180 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को सौंप दिया था।

दो टूक : पाक ड्रोन घुसपैठ तुरंत बंद करे

सेना प्रमुख ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से ड्रोन घुसपैठ तुरंत रोकने को कहा है। मंगलवार को भारत-पाक के डीजीएमओ में फोन पर बातचीत हुई, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया। उन्होंने दो टूक कहा कि पाक को साफ कर दिया गया है कि यह अस्वीकार्य है। वह ऐसी गतिविधियों पर तुरंत लगाम लगाए।

राजौरी में दिखे ड्रोन : इस बीच, राजौरी में एलओसी के पास कई संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन की हलचल देखी गई। भारतीय सेना ने जवाबी फायरिंग की जिसके बाद ड्रोन वापस लौट गए। इससे पहले रविवार को पुंछ जिले में भी पाकिस्तानी ड्रोन दिखे थे। शनिवार से अब तक कम से कम आठ ड्रोन भारतीय सीमा के पास देखे गए हैं।

'यूपीआई के वैश्विक विस्तार के प्रयास'

हर्ष कुमार
नई दिल्ली, 13 जनवरी

एम नागराजू, वित्तीय सेवा सचिव

वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने मंगलवार को कहा कि सरकार स्वदेशी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है। पूर्वी एशिया के बाजारों में इसकी पहुंच का विस्तार करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

ग्लोबल इन्क्लूसिव फाइनैंस इंडिया समिट में बोलते हुए उन्होंने कहा, 'यूपीआई के कारण आज भारत में लगभग 50 प्रतिशत डिजिटल लेनदेन हो रहा है। हमने कुछ देशों में विस्तार किया है और अब इसे कई अन्य देशों, खासकर पूर्वी एशिया में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।' नागराजू ने कहा कि यूपीआई पहले ही भूटान, सिंगापुर, कतर, मॉरिशस, नेपाल और संयुक्तअरब अमीरात (यूएई), श्रीलंका और फ्रांस सहित 8 देशों में चल रहा है। इससे भारत के यात्रियों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा मिल रही है। नागराजू ने छोटी और सूक्ष्म इकाइयों को मध्यम उद्यमों में बदलने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। देश में कई करोड़ इकाइयों की उपस्थिति के बावजूद सूक्ष्म इकाइयों का मध्यम और बड़े उद्यमों में रूपांतरण नहीं हो रहा है। दरअसल देश में सूक्ष्म इकाइयां मझोले और बड़े उद्योगों में परिवर्तित नहीं हो रही हैं, जबकि कई करोड़ इकाइयां मौजूद हैं। मुझे लगता है कि ऐसा तभी होगा, जब सूक्ष्म उद्यमों को समर्थन, बाजार तक पहुंच और उत्पादकता का लाभ मिले।

भारत दो साल से भी कम समय में हुआ था पोलियोमुक्त

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत के जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में मंगलवार को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई। देश में पोलियो वायरस का आखिरी मामला सामने आए 15 साल पूरे हो गए। 2009 में भारत में पोलियो के 741 मामले थे, जो उस समय वैश्विक कुल मामलों का 60 प्रतिशत थे। हालांकि, संसाधनों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण देश में दो साल से भी कम समय में पोलियो का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। आखिरी मामला 2011 में सामने आया था।

इंटरनेशनल पीडियाट्रिक एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक डा. नवीन ठक्कर ने कहा कि भारत में पोलियो का आखिरी मामला दर्ज होने के 15 साल बाद, 'हमें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किए गए असाधारण प्रयासों की याद आती है। फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं ने हर समुदाय में विश्वास जगाया और देश ने इतने बड़े पैमाने पर टीके वितरित किए, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।"

10 मिनट वाली डिलीवरी पर ब्रेक, ब्लिंकिट-स्विगी को निर्देश

एजेंसियां, नयी दिल्ली

देश में 'क्विक कॉमर्स' के नाम पर चल रही 10 मिनट की अंधी दौड़ पर अब ब्रेक लगने वाला है. केंद्रीय श्रम मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद 'ब्लिंकिट' ने अपने सभी मंचों से 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटा लिया है. माना जा रहा है कि स्विगी और जेप्टो जैसे अन्य दिग्गज भी जल्द ही इस कदम का अनुसरण करेंगे. दरअसल, सरकार इतनी कम समय सीमा में सामान पहुंचाने वाले डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा और उनके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थी. सरकार का मानना है कि 10 मिनट की समय सीमा न केवल सड़क सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि यह गिग वर्कर्स पर अमानवीय दबाव भी डालती है. हालांकि, जोमैटो (इटर्नल ग्रुप) के सीइओ दीपिंदर गोयल ने स्पष्ट किया था कि यह गति स्टोर की नजदीकी के कारण है, न कि तेज ड्राइविंग की वजह से. लेकिन सरकार के कड़े रुख के बाद कंपनियों को अपनी ब्रांडिंग बदलनी पड़ रही है. अब फोकस केवल तेज डिलीवरी पर नहीं, बल्कि उत्पादों की रेंज और कर्मचारियों की सुरक्षा पर स्थानांतरित हो रहा है.

ब्लिंकिट ने बदली अपनी टैग लाइन

ब्लिंकिट ने अपनी चर्चित टैग लाइन को पूरी तरह बदल दिया है. पहले कंपनी '10 मिनट में 10,000 से अधिक उत्पाद पहुंचेंगे' का दावा करती थी, जिसे अब बदलकर '30,000 से अधिक उत्पाद आपके दरवाजे पर पहुंचेंगे' कर दिया गया है. कंपनी ने अब समय के बजाय उत्पादों की विविधता (वैरायटी) को अपनी ताकत के रूप में पेश करना शुरू किया है. प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से भी 10 मिनट वाली ब्रांडिंग हटा ली गई है.

सड़क पर सुरक्षा थी बड़ी चिंता

डिलीवरी पार्टनर्स और श्रम विशेषज्ञों का तर्क था कि 10 मिनट का टाइमर सड़क पर असुरक्षित ड्राइविंग का सबसे बड़ा कारण बनता है. हालांकि कंपनियां दावा करती हैं कि ऐप पर टाइमर नहीं दिखाया जाता, लेकिन 'कस्टमर रेटिंग' और 'डिलीवरी टारगेट' का दबाव कर्मियों को जोखिम लेने पर मजबूर करता है. मंत्रालय के साथ हुई चर्चा में मुख्य मुद्दा यही था कि गिग वर्कर्स के लिए बेहतर कामकाजी परिस्थितियां और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके. साल 2025 में क्रिसमस और नव वर्ष की पूर्व संध्या पर, गिग कर्मियों ने देशव्यापी हड़ताल कर दी थी.

15 लाख से अधिक ऑर्डर भारत में रोजाना डिलीवर किए जा रहे

1.27 करोड़ गिग वर्कर्स भारत में कर रहे हैं काम

450 से 650 रुपये के बीच एक औसत भारतीय ग्राहक का सिंगल ऑर्डर

64 हजार करोड़ रुपये का सालाना कारोबार भारत में

4.5 लाख से अधिक डिलीवरी पार्टनर्स अकेले जोमैटो और ब्लिंकिट के

INTERNATIONAL

टैरिफ पर तनाव, लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स सुरक्षित करने में साथ हैं भारत व अमेरिका

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आयात शुल्क को लेकर भारत और अमेरिका के बीच भले ही तनाव चल रहा हो, पर क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर दोनों देशों सहमत हैं। एक दिन पहले दिल्ली में अमेरिका के नये राजदूत सर्जियो गोर ने क्रिटिकल मिनरल्स पर नये संगठन 'पैक्स सिलिका' का सदस्य बनने का प्रस्ताव भारत के समक्ष रखा। कुछ ही देर बाद वाशिंगटन में अमेरिकी वित्त मंत्री स्काट बेसेंट की अगुवाई में हुई लोकतांत्रिक देशों की बैठक में भारत के रेलवे और आइटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हिस्सा लिया है।

इस बैठक को दुनिया में क्रिटिकल मिनरल्स के खानों और प्रसंस्करण पर चीन के बढ़ते दबदबे के खिलाफ लोकतांत्रिक देशों को एकजुट करने के तौर पर माना जा रहा है, ताकि सेमीकंडक्टर, सौर ऊर्जा और अन्य प्रौद्योगिकी आधारित मैन्यूफैक्चरिंग के लिए दुर्लभ धातुओं की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। बैठक में जापान, इजरायल, कनाडा, ब्रिटेन, इटली, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, फ्रांस के वित्त मंत्रियों ने हिस्सा लिया।

बैठक में सभी सहभागी देशों ने शोध और अनुसंधान साझा करने पर सहमति जताई, ताकि क्रिटिकल मिनरल्स की खोज, निष्कर्षण व प्रसंस्करण में सहयोग बढ़ाया जा सके। वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए बैठक को जरूरी बताते हुए अमेरिकी सरकार ने कहा है कि "चर्चा के दौरान सभी प्रतिभागियों ने एकमत से इस बात पर जोर दिया कि अहम खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं में प्रमुख कमजोरियों को जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए।"

स्काट बेसेंट ने आशा व्यक्त की है कि देश जोखिम कम करने की नीति अपनाएंगे और वे अहम खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में वर्तमान कमियों को ठीक करने की जरूरत को भली-भांति समझते हैं। दुर्लभ खनिज के 60 से 90 प्रतिशत वैश्विक भंडारों पर कब्जा जमाए चीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये आपूर्ति श्रृंखलाएं अब काफी हद तक केंद्रित हो चुकी हैं, जिससे व्यवधान पैदा करने या हेरफेर करने की संभावना बढ़ गई है।

- वाशिंगटन में अमेरिका की अगुवाई में हुई लोकतांत्रिक देशों की अहम बैठक
- वअमेरिकी वित्त मंत्री स्काट बेंसेंट ने की अध्यक्षता, अश्विनी वैष्णव हुए शामिल

वाशिंगटन डीसी में मंगलवार को अमेरिका के वित्त मंत्री स्काट बेसेंट(दाएं से छठे) की अगुवाई में जी7 देशों के वित्त मंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव(बाएं से दूसरे)।एएनआइ

> सुरक्षित क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन विकसित भारत के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है। हमने विभिन्न देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। इसमें शोध साझा करना और नई तकनीकों का विकास शामिल है।
>
> – अश्विनी वैष्णव, आइटी मंत्री

अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद कहा, "सुरक्षित क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन विकसित भारत के लक्ष्य के लिए अहम है। हमने बैठक में विभिन्न देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की, जिसमें शोध साझा करना और नई तकनीकों का विकास शामिल है।" कहा कि भारत इन खनिजों की घरेलू खोज को बढ़ावा दे रहा है और वैश्विक साझेदारी से इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करेगा। अमेरिकी सरकार की तरफ से 60 और भारत सरकार की तरफ से 35 दुर्लभ धातुओं को चिन्हित किया गया है जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, रेअर अर्थ एलिमेंटस, सिलिकान, कापर, बेरेलियम, जर्मेनियम, बिस्मथ आदि शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आइईए) की 'ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स आउटलुक 2025' रिपोर्ट के अनुसार, चीन 20 में से 19 प्रमुख खनिजों की रिफाइनिंग में प्रमुख भूमिका निभाता है, जहां उसकी औसत बाजार हिस्सेदारी करीब 70 प्रतिशत है। विशेष रूप से, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के खनन और रिफाइनिंग में चीन का 70 से 90 प्रतिशत नियंत्रण है, जो सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहनों, इलेक्ट्रानिक्स, सौर ऊर्जा पैनल आदि के निर्माण में बेहद जरूरी है। बैट्रियों व उर्जा भंडारण के लिए जरूरी लिथियम की रिफाइनिंग में 60 प्रतिशत और सिंथेटिक ग्रेफाइट में 90 प्रतिशत से अधिक का प्रभुत्व चीन का है। आइईए की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक चीन की हिस्सेदारी और बढ़ सकती है।

भारत को टैरिफ की कम, चाबहार पोर्ट की ज्यादा चिंता

जयप्रकाश रंजन • जागरण

नई दिल्ली : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा से वैश्विक व्यापार में हलचल बढ़ी है, पर भारत पर इसका सीधा असर सीमित रहने की संभावना है। इसकी वजह यह है कि भारत ने बीते वर्षों में ईरान संग व्यापारिक रिश्ते पहले ही काफी घटा दिए हैं। पिछले वित्त वर्ष में भारत-ईरान द्विपक्षीय व्यापार महज 1.6 अरब डालर रहा, जबकि भारत के कुल निर्यात में ईरान की हिस्सेदारी 0.15 प्रतिशत है। ईरान भारत के शीर्ष 50 कारोबारी साझेदार देशों में भी नहीं है।

- ईरान पर तमाम प्रतिबंधों के बीच अमेरिका ने चाबहार पर भारत को अप्रैल 2026 तक दे रखी है राहत
- अमेरिका-ईरान तनाव और बढ़ने पर ट्रंप प्रशासन चाबहार पोर्ट को भी प्रतिबंधों के दायरे में ला सकता है

इसके बावजूद भारत की सबसे बड़ी चिंता चाबहार पोर्ट को लेकर है। ईरान स्थित इस बंदरगाह का विकास भारत कर रहा है और अमेरिका ने इसे अप्रैल 2026 तक प्रतिबंधों से छूट दे रखी है। यदि अमेरिका और ईरान के बीच संबंधों में तनाव और बढ़ता है, तो डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन चाबहार को भी प्रतिबंधों के दायरे में ला सकता है, जिससे भारत के रणनीतिक हित प्रभावित हो सकते हैं। भारत ने भारी अमेरिकी दबाव के बावजूद ईरान के साथ कूटनीतिक संपर्क बनाए रखे हैं। कभी भारत के शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल रहा ईरान, खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता के समय भारत के लिए अहम विकल्प रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक ने कई अवसरों पर ईरान के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों की दुहाई दी है। नरेन्द्र मोदी ने अक्टूबर, 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से मुलाकात की थी। वर्ष 2025 में ईरानी राष्ट्रपति को आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली आना था। इसे लेकर कार्यक्रम भी तय हो गया था पर अंतिम समय में कार्यक्रम स्थगित हो गया था।

बासमती निर्यात पर असर, 2000 करोड़ फंसने की आशंका

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

ईरान में जारी राजनीतिक उथल-पुथल का सीधा असर भारत के बासमती चावल निर्यात पर पड़ता दिख रहा है। निर्यातकों के अनुसार ईरान भेजे जा चुके चावल के भुगतान को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है और अनुमान है कि वहां के बाजार में करीब 2000 करोड़ रुपये फंसे हो सकते हैं। हालात यह हैं कि कई मामलों में ईरानी खरीदारों से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है।

इंडियन राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन (आइआरईए) ने निर्यातकों को ईरान के साथ नए सौदे बेहद सोच-समझकर करने की सलाह दी है। ईरान को निर्यात में आई कमी का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा है, जहां बासमती चावल के दाम पांच से सात रुपये प्रति किलो तक गिर गए हैं। फेडरेशन ने निर्यातकों से पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के वैकल्पिक बाजारों पर फोकस बढ़ाने को कहा है, क्योंकि चावल निर्यात से किसानों की आय भी सीधे तौर पर जुड़ी है।

आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल-नवंबर के दौरान भारत ने ईरान को 46.8 करोड़ डालर मूल्य का 5.99 लाख टन बासमती चावल निर्यात किया। पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 75 करोड़ डालर का रहा था। आइआरईए के अध्यक्ष प्रेम गर्ग के अनुसार, भुगतान में देरी और अनिश्चितता के कारण घरेलू मंडियों में कीमतों पर दबाव बढ़ा है। 1121 किस्म का बासमती जहां 85 से घटकर 80 रुपये प्रति किलो पर आ गया है, वहीं 1401 किस्म 85 से गिरकर 78 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है।

इस बीच अमेरिका द्वारा ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की चेतावनी भी चिंता का विषय बनी हुई है। हालांकि एफआइईओ का कहना है कि अमेरिका को भारत के चावल निर्यात पर पहले से ही 50 प्रतिशत शुल्क लग रहा है और इसके बावजूद निर्यात में कोई खास गिरावट नहीं आई है। संगठन के मुताबिक भारत-ईरान के बीच सालाना 1.68 अरब डालर का व्यापार होता है, जिसमें अधिकांश हिस्सा कृषि उत्पादों का है।

जटिल वैश्विक परिदृश्य में ब्रिक्स महत्वपूर्ण मंच

विदेश मंत्री जयशंकर ने 'ब्रिक्स 2026' के लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया

चीन, रूस समेत 10 देशों वाले संगठन ब्रिक्स की इस वर्ष अध्यक्षता कर रहा है भारत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिनों-दिन गहराती वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर रहने वाले देशों चीन, रूस, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील की सदस्यता वाले संगठन ब्रिक्स को एक महत्वपूर्ण मंच बताया है जहां बातचीत और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। भारत वर्ष 2026 में 10 देशों के ब्रिक्स संगठन की अध्यक्षता कर रहा है।

मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक समारोह में 'ब्रिक्स 2026' के लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया। नए लोगो को कमल के फूल से प्रेरित किया गया है, जो कि गहरे जड़ों वाली विरासत और बढ़ती सहनशीलता का प्रतीक है। इसकी पंखुड़ियां ब्रिक्स देशों के रंगों को दर्शाती हैं, जोकि एक साझा उद्देश्य के तहत एकत्रित कई आवाजों का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रतीक के केंद्र में नमस्ते का इशारा है जो सम्मान और सहयोग का आह्वान करता है। इस दौरान जयशंकर ने कहा -'वर्तमान वैश्विक परिवेश जटिल है व यह चुनौती पेश कर रहा है। भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं, जटिल आर्थिक परिदृश्य, जलवायु संबंधित जोखिम, तकनीकी बदलाव और लगातार विकास संबंधी भेदभाव देशों को प्रभावित कर रहे हैं।

इस संदर्भ में ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है जो संवाद, सहयोग और विकास को प्रोत्साहित करता है, व्यावहारिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देता है तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और विकास के विभिन्न चरणों को ध्यान में रखता है।'

विदेश मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन भारत वैसे ही धूमधाम से करने जा रहा है जैसा कि वर्ष 2023 में जी-20 सम्मेलन का किया गया था। आज जिस तरह से विदेश मंत्रालय ने इसके 'लोगो' के अनावरण का कार्यक्रम का आयोजन किया उससे यह संकेत भी मिलता है। इसमें ब्रिक्स के सभी दस सदस्य देशों के राजदूतों के अलावा दूसरे कई देशों के राजदूतों व मिशन हेड को भी आमंत्रित किया गया था। सनद रहे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कई बार ब्रिक्स की गतिविधियों को लेकर अपनी सख्त नाराजगी जता चुके हैं। जुलाई, 2025 में उन्होंने ब्रिक्स देशों पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत का टैरिफ लगाने की भी घोषणा की थी। वह आरोप लगाते हैं कि ब्रिक्स के सदस्य देश अपनी अलग करेंसी चलाने की कोशिश में है ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डालर को कमजोर किया जा सके। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संभवतः जुलाई या अगस्त में कराये जाने की बात हो रही है और इसके लिए चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के भी भारत आने की संभावना है। बता दें कि ब्रिक्स में भारत, चीन, रूस, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील के अलावा मिस्र, इथियोपिया, यूएई और इंडोनेशिया शामिल हैं। इसके अलावा बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान को ब्रिक्स के साझेदार देशों के रूप में शामिल किया गया है।

विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि वैश्विक वास्तविकताओ को देखते हुए वर्षों से ब्रिक्स ने अपने एजेंडे और सदस्यता का विस्तार किया है जबकि आम जन केंद्रित विकास, संवाद को बढ़ावा देने और व्यावहारिक सहयोग पर फोकस बनाए रखा है। भारत की कोशिश होगी कि वैश्विक उथल-पुथल का सामना करने में सक्षम संरचनात्मक संस्थागत शक्तियों का निर्माण करने का प्रयास किया जाए। भारत ब्रिक्स भागीदारों के साथ मिलकर कृषि, स्वास्थ्य, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखलाओं में लचीलापन विकसित करने पर काम करेगा।

नई दिल्ली में मंगलवार को ब्रिक्स 2026 की वेबसाइट, लोगो और थीम की लांचिंग के मौके पर बोलते विदेश मंत्री एस जयशंकर।एएनआइ

- जयशंकर ने ब्रिक्स को सहयोग व विकास के लिए महत्वपूर्ण फोरम करार दिया

20 वीं वर्षगांठ मनाएगा इस वर्ष ब्रिक्स, भारत की अध्यक्षता वैश्विक कल्याण को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगी

40 40 प्रतिशत है वैश्विक जीडीपी में ब्रिक्स देशों का योगदान, विश्व की 49.5 प्रतिशत जनसंख्या इन देशों में रहती है

ट्रंप ने बढ़ाया दबाव, ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने का विधेयक पेश

- सीनेट में रिपब्लिकन सांसद रैंडी फाइन ने पेश किया ग्रीनलैंड एनक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट बिल
- अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस और विदेश मंत्री रूबियो से मिलेंगे डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री

वाशिंगटन, एएनआइ: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर "कुछ करने" की धमकी के बीच अमेरिकी कांग्रेस में बड़ा राजनीतिक कदम सामने आया है। फ्लोरिडा से रिपब्लिकन सांसद रैंडी फाइन ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने और आगे चलकर उसे अमेरिकी राज्य बनाने से जुड़ा 'ग्रीनलैंड एनक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट' पेश किया है। यह विधेयक राष्ट्रपति को ग्रीनलैंड को अमेरिकी संघ में लाने के लिए जरूरी साधनों" का उपयोग करने का अधिकार देने का प्रस्ताव करता है। वहीं, ग्रीनलैंड को अमेरिकी कब्जे में जाने से रोकने में डेनमार्क व ग्रीनलैंड जी जान से जुटे हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्री बुधवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस व विदेश मंत्री मार्को रूबियों से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के हिस्से में नहीं आया तो आज नहीं तो कल वह रूस या चीन के कब्जे में चला जाएगा, जो कि अमेरिका या यूरोप के लिए अच्छी बात नहीं होगी।

क्या खास होगा विधेयक में: विधेयक के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को डेनमार्क से बातचीत कर ग्रीनलैंड को अमेरिकी क्षेत्र के रूप में हासिल करने का अधिकार दिया जाएगा। राष्ट्रपति को कांग्रेस के समक्ष रिपोर्ट पेश करनी होगी, जिसमें कानूनी बदलावों का विवरण होगा। यह प्रक्रिया इस शर्त पर आधारित होगी कि ग्रीनलैंड ऐसा संविधान अपनाए जो अमेरिकी संविधान के अनुरूप और गणतांत्रिक स्वरूप का हो।

ट्रंप का नया दांव: ईरान सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए किया फैसला

ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ थोपा

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार देर रात ईरान से किसी भी तरह के व्यापार पर रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान से व्यापार करने वाला कोई भी देश अमेरिका के साथ अपने व्यापार पर 25 फीसदी टैरिफ देगा। उन्होंने कहा कि यह आदेश अंतिम है और इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा।

ईरान में दो हफ्ते से ज्यादा समय से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रंप का यह कदम सीधे तौर पर ईरान की सरकार पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया है, लेकिन इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। भारत, चीन, रूस, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश ईरान के बड़े व्यापारिक भागीदार हैं। ऐसे में इन देशों को अब अमेरिका और ईरान के बीच एक को चुनने की मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।

अमेरिका ने भारत पर पहले ही 50 फीसदी टैरिफ लगा रखा है। नया टैरिफ भारत-अमेरिका के संबंधों में तनाव बढ़ा सकता है। हालांकि, ट्रंप ने यह नहीं बताया कि इस नीति को कैसे लागू किया जाएगा। इस आदेश ने दुनिया के बड़े हिस्से में हलचल पैदा कर दी है।

ईरान से ₹1.68 बिलियन डॉलर का व्यापार : भारत-ईरान के बीच लंबे समय से व्यापारिक संबंध हैं। बीते कुछ समय में ईरान के कच्चे तेल पर प्रतिबंध के बाद दोनों देशों में व्यापार का स्वरूप बदला है। व्यापार का दायरा अब गैर तेल उत्पादों में बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार लगभग 1.68 बिलियन डॉलर रहा था।

सबसे बड़ा बासमती खरीदार : ईरान भारत का सबसे बड़ा बासमती चावल खरीदार है। भारत ने 2025-26 के अप्रैल-नवंबर के दौरान ईरान को 468.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बासमती चावल निर्यात किया, जिसकी कुल मात्रा 5.99 लाख टन थी।

चाबहार को लेकर दुविधा बढ़ेगी : चाबहार बंदरगाह का विकास भारत-ईरान द्वारा संपर्क एवं व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। पहले अमेरिका इस पर सख्त था, लेकिन हाल में भारत को परिचालन जारी रखने के लिए छह महीने छूट दी गई थी। यह प्रतिबंध छूट 29 अक्तूबर से प्रभावी है। ➤ देखें P 18

ट्रंप ने कहा, प्रतिष्ठानों पर कब्जा करें प्रदर्शनकारी

ईरान में विरोध के बीच ट्रंप ने ईरानी अधिकारियों संग बैठक रद्द कर दी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा, संघर्ष जारी रखो, मदद रास्ते में है। उन्होंने कहा कि ईरानी देशभक्तों कातिलों और अत्याचारियों के नाम सुरक्षित रखो, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ➤ देखें P 20

भारत से ईरान जाने वाले उत्पाद

भारत से ईरान को मुख्य रूप से कृषि और उपभोक्ता उत्पाद भेजे जाते हैं। इसमें बासमती चावल एक अहम उत्पाद है। इसके अलावा चाय और चीनी की भी ईरान में अच्छी खासी मांग है। भारतीय दवाइयों की भी वहां मार्केट में मजबूत हिस्सेदारी है। फल और अन्य खाद्य उत्पाद भी भारत के प्रमुख निर्यात उत्पाद हैं।

दोनों देशों का व्यापार (अरब डॉलर में)

वर्ष	निर्यात	आयात	द्विपक्षीय व्यापार
2018-19	3.51	13.53	17.03
2019-20	3.38	1.39	4.77
2020-21	1.77	0.33	2.10
2021-22	1.45	0.46	1.91
2022-23	1.66	0.67	2.33
2023-24	1.22	0.62	1.85
2024-25	1.24	0.44	1.68

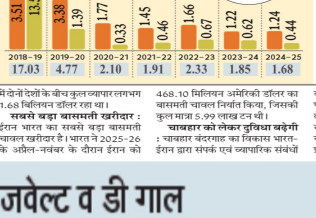

ईरान से आयात

ईरान से भारत मुख्य रूप से खजूर और सूखे मेवे आयात करता है इसमें पिस्ता और बादाम शामिल हैं। इसके अलावा कुछ पेट्रोकेमिकल उत्पाद भी भारत आते हैं। पहले ईरान भारत का बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते तेल आयात लगभग बंद हो गया।

इन देशों पर सबसे ज्यादा असर

- **चीन :** ईरान का सबसे बड़ा तेल और व्यापारिक साझेदार
- **यूरोपीय यूनियन :** जर्मनी और इटली जैसे यूरोपीय देश ईरान से करते हैं व्यापार
- **तुर्किये :** ईरान से तेल और गैस आयात करता है
- **यूएई :** ईरान का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार
- **रूस :** सैन्य, ऊर्जा, परिवहन क्षेत्रों में मिलकर काम करते हैं
- इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देश भी ईरान से व्यापार करते हैं

कैसाब्लांका सम्मेलन में मिले चर्चिल, रूजवेल्ट व डी गाल

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में आज ही मोरक्को में ब्रिटिश पीएम चर्चिल, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट व फ्रांसीसी जनरल डी गाल ने मुलाकात की थी। नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि मित्र राष्ट्र धुरी शक्तियों के बिना शर्त आत्मसमर्पण से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे।

EDITORIAL

भारत से जुड़ाव बढ़ाने को बेताब जर्मनी

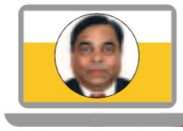

टीसीए रंगाचारी | पूर्व राजनयिक

एक अच्छी विश्व व्यवस्था का हिमायती हिन्दुस्तान भी है और जर्मनी भी। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज इसे बखूबी समझ रहे हैं और उनकी भारत यात्रा से रिश्तों को मजबूती मिली है।

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का पद संभालने के कुछ महीनों के भीतर ही एशिया की अपनी पहली यात्रा के रूप में भारत को चुनना इस बात का संकेत है कि बर्लिन अब नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों को कितना महत्व देता है। अक्तूबर 2024 में, जर्मन कैबिनेट ने 'फोकस ऑन इंडिया' नाम से एक पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि भारत के साथ सहयोग को जर्मनी एक ऐसे अवसर के रूप में देखता है, जिससे वह अपने उद्देश्यों को पा सकता है।

सहयोग का यह दायरा कई क्षेत्रों में फैला हुआ है- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक। इसे आकार और आधार देते हैं- लोकतंत्र, कानून का शासन और मानवाधिकार-पालन के साझा मूल्य। साथ ही, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, शिक्षा और लोगों के आपसी संपर्क से भी इस सहयोग को गति मिल रही है। भारत के लिए यह रिश्ता महत्वपूर्ण है। साझा मूल्य (विशेषकर लोकतांत्रिक मूल्य), लोगों में आपसी संपर्क, सुरक्षा, शिक्षा, आर्थिक व्यापार, विज्ञान और तकनीक ऐसे क्षेत्र हैं, जहां हमें इसका फायदा मिलेगा। मर्ज की यात्रा बताती है कि अब जर्मनी ने भी भारत से अपने रिश्ते को फायदेमंद माना है। इससे द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूती मिलेगी।

बर्लिन की बदलती सोच आने वाले दिनों के लिए शुभ है। इसी नींव पर ऐसी कई सारी चीजें खड़ी हो सकती हैं, जिनसे द्विपक्षीय रिश्ते नई ऊंचाइयों को छू सकें। कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर दोनों देश एक-दूसरे का महत्व अब समझने लगे हैं। विशेषकर, नियम-आधारित एक अच्छी विश्व व्यवस्था का हिमायती हिन्दुस्तान भी है और जर्मनी भी।

हम चाहते हैं कि भारत के कुशल कामगारों को जर्मनी में काम के अवसर मिल सकें और इस राह की पाबंदियां जल्द हटाई जाएं। मर्ज का दौरा इस लिहाज से सुखद रहा, क्योंकि वीजा को लेकर इसमें सहमति बनी है। यह जरूर है कि 2022 की तरह इस समझौते में भी 'इंटेन्ट', यानी 'हमारा इरादा है' जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन इससे आगे की राह तैयार होगी। दोनों देशों में बनी सहमति के मुताबिक, अब जर्मन एयरपोर्ट से गुजरने पर भारतीयों को 'ट्रांजिट वीजा' नहीं लगेगा। इससे लोगों के आपसी संपर्क सुधर सकेंगे।

गौरतलब है, पूरे यूरोप में प्रवासन एक बड़ा मुद्दा है। जर्मनी अपवाद नहीं है। उसकी दिक्कत यह है कि जर्मन मूल के लोग धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। जर्मनी की आबादी अभी करीब 8.5 करोड़ है, जिसमें लगभग 10 फीसदी हिस्सा विदेशी मूल के लोगों का है, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके उलट, जर्मनी में प्रतिस्थापन दर एक प्रतिशत से भी नीचे चली गई है, जबकि इसका 2.1 फीसदी रहना जरूरी माना जाता है। इसका सीधा अर्थ है कि यहां भविष्य में जर्मन आबादी घटती जाएगी, जिससे सामाजिक सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ सकता है।

यह हमारे लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। हिन्दुस्तानियों के साथ जर्मन लोगों को कोई दिक्कत पेश नहीं आती। इसका एक बड़ा उदाहरण नर्सिंग है। वहां भारतीय नर्सों की आमद को लेकर मैंने करीब दो दशक पहले काफी प्रयास किए थे, जब मैं वहां अपनी सेवा दे रहा था। हालांकि, उन दिनों वीजा नियम सरल नहीं थे, जिसके कारण यह संभव नहीं हो पाया, लेकिन अब वीजा नियम आसान बनाने से परिस्थितियां बदल सकती हैं।

जर्मनी में अवसरों का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि जर्मन भाषा में कुशलता पाई जाए। यही कारण है कि मैं भारत में अंग्रेजी के साथ जर्मन और फ्रांसीसी सीखने की वकालत करता हूं। बर्लिन में अभी 2.75 लाख भारतीय रहते हैं, जो अमूमन कम समय के लिए जाते हैं। कई लोग इसलिए वहां नहीं जा पाते, क्योंकि उनको जर्मन नहीं आती, जबकि भाषायी दक्षता के साथ-साथ यदि आपके पास विज्ञान में जरूरी डिग्री हो, तो वहां नौकरी पाना आसान हो सकता है। पहले दोनों देश एक-दूसरे की डिग्री को मान्यता नहीं देते थे, लेकिन अब इस मामले में भी बातचीत आगे बढ़ी है।

इसी तरह, रक्षा सौदा भी इस दौरे की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वास्तव में, तकनीक में जर्मनी काफी आगे है। जर्मन चांसलर की यात्रा में सह-विकास और सह-उत्पादन पर सहमति बनी है। बर्लिन अब नई दिल्ली के साथ रक्षा सौदा कर रहा है। यह हमारे लिए उपयोगी होगा। यहां यह सवाल उठ सकता है कि क्या यूरोप के अन्य देश भी इस तरह के समझौते हमारे साथ कर सकते हैं? निस्संदेह वे ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यूरोपीय संघ के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते की शर्तें अलग होंगी, जबकि द्विपक्षीय समझौतों की अलग होती हैं।

मर्ज के दौरे में पनडुब्बियों के साझा निर्माण पर हुआ समझौता एक बड़ा कदम माना जाएगा। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा मुहैया कराने वाला एक प्रमुख देश है। हिंद महासागर में समुद्री डकैती और ऐसे ही दूसरे खतरों के खिलाफ भी नई दिल्ली एक बड़ी सुरक्षा गारंटी है। इस समझौते से इस क्षेत्र को समुद्री गतिविधियों में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिलेगी। समुद्री रास्तों की सुरक्षा भी इसी में शामिल है। इससे 'क्वाड' का एक महत्वपूर्ण मकसद भी पूरा हो सकेगा। क्वाड दरअसल भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक समूह है, जिसका मुख्य उद्देश्य एक स्वतंत्र, खुला और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना है। सुरक्षा सहयोग में और भी कई संभावनाएं हैं, जिसकी झलक आतंकवाद से लड़ने को लेकर भारत-जर्मनी संयुक्त वक्तव्य में जताई गई प्रतिबद्धता से मिलती है। देखा जाए, तो स्थिरता और सुरक्षा प्रगति व खुशहाली के लिए जरूरी है, और दोनों देश यही चाहते हैं।

हालांकि, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। भले ही भारत-जर्मनी के बीच 50 अरब डॉलर से कुछ अधिक का सालाना कारोबार होता है, लेकिन चीन के मुकाबले यह चार गुना कम है। उल्लेखनीय है कि जर्मनी का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार अमेरिका था, पर बीते साल चीन ने उससे यह ओहदा छीन लिया है। साल 2025 के शुरुआती 10 महीनों में 173 अरब डॉलर से अधिक का कारोबार दोनों देशों कर चुके थे, जो 2024 के इसी अवधि से 3.5 प्रतिशत अधिक था। यह बताता है कि हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसे में, मर्ज का दौरा नए साल में एक अच्छी शुरुआत है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

Hindustan Page

वीबी-जी राम जी से जुड़े वादे और चुनौतियां

लगभग दो दशकों से, भारत की नीतिगत व्यवस्था में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की एक खास जगह थी। इसका आर्थिक महत्त्व एक सरल लेकिन महत्त्वपूर्ण संस्थात्मक विचार में था कि ग्रामीण संकट की स्थिति में इसे राज्य से मदद पाने के अधिकार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी ग्रामीण परिवार जो शारीरिक श्रम करने को तैयार हो वह 100 दिन तक रोजगार की मांग कर सकता था और प्रशासन को समय पर यह दायित्व पूरा करना होता था।

नागरिक की दावेदारी और राज्य के दायित्व के इस फर्क ने इस कार्यक्रम को सिर्फ एक बजट से जुड़ा हस्तक्षेप नहीं रहने दिया। इसने श्रम बाजार के निचले स्तर पर अस्थिरता से बचाव के लिए एक बीमा के तौर पर काम किया, भले ही यह परिपूर्ण न हो। वित्त वर्ष 2024-25 में, मनरेगा ने 2.9 अरब कार्य दिवस का रोजगार दिया जिसमें कुल लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 58.15 फीसदी थी।

अब, इस व्यवस्था में अचानक बदलाव लाकर विकसित इसे भारत-गारंटी फॉर रोजगार ऐंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025 कर दिया गया है जो इस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को एक पुनर्गठित संस्थागत ढांचे में बदल देता है। सरकार ने इस सुधार को आधुनिकीकरण के तौर पर पेश किया है जिसमें अधिक रोजगार दिवसों की गारंटी, टिकाऊ संपत्ति बनाने पर जोर, कड़ी निगरानी और विकास प्राथमिकताओं के साथ बेहतर तालमेल जरूरी है। लेकिन, इससे एक अलग बदलाव दिखता है और वह बदलाव यह है कि अनिश्चितता के दौर के लिए डिजाइन की गई योजना अब नियंत्रण से जुड़े बदलाव में तब्दील हो गई है।

यह अधिनियम ग्रामीण परिवार की प्रति वर्ष रोजगार पात्रता को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करता है। सैद्धांतिक रूप में, यह परिवारों के लिए आय सुरक्षा को बढ़ाता है। लेकिन, कानूनी सीमा शायद ही कभी बाध्यकारी रही है। प्रति परिवार को दिया गया औसत रोजगार 2024-25 में 50.24 दिन ही था और पिछले चार वर्षों में भी लगभग ऐसा ही था, जिससे पता चलता है कि प्रभावशीलता इस बात से अधिक तय होती है कि मांग की फंडिंग कैसे की जाए, स्वीकृति कैसे मिले, इसे काम में कैसे बदला जाए न कि दिनों की संख्या से। इन बुनियादी तंत्रों में बदलाव किए बिना, कानूनी पात्रता दिनों को बढ़ाना काफी हद तक प्रतीकात्मक रहेगा।

अमरेंदु नंदी

अधिनियम बनाई गई संपत्तियों की असमान गुणवत्ता और टिकाऊपन की समस्या को भी हल करना चाहता है। वीबी-जी राम जी जल संरक्षण, जलवायु अनुकूलन और बुनियादी ढांचे से जुड़े कामों को एकत्रित करने का प्रस्ताव करती है और उन्हें ग्राम विकास योजनाओं से जोड़ती है। भारत में, जहां जलवायु झटके कृषि उत्पादन और ग्रामीण आय को तेजी से बाधित कर रहे हैं, पानी की उपलब्धता को स्थिर करने या बाढ़ और सूखे से बचाने वाले निवेश तत्काल मजदूरी की प्रेरणा से परे लाभ दे सकते हैं।

मांग-संचालित रोजगार गारंटी योजना को तेजी से लागू होने वाला साधन बने रहना चाहिए। इसकी ताकत श्रम का जल्दी उपयोग करने में होनी चाहिए खासतौर पर तब जब परिवारों को निजी झटकों का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत, उच्च-गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के लिए तकनीकी डिजाइन, सही क्रम और लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। वीबी-जी राम जी के तहत पूरा जोर अधिक जटिल परिसंपत्तियों पर है तो इसमें जोखिम यह है कि यह संकट के समय कम लचीली हो सकती है। इस बदलाव से यह योजना बीमा की तरह कम और निवेश की तरह ज्यादा हो जाएगी। इससे शायद औसतन ज्यादा फायदा हो लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब ये उतनी जल्दी काम नहीं आएगी।

हालांकि, इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण वित्तीय बदलाव है। मनरेगा के तहत, फंडिंग मांग पर आधारित थी। जब ग्रामीण संकट बढ़ा यानी सूखा पड़ने, बाढ़ आने या आर्थिक झटकों के बाद इसका व्यय अपने आप बढ़ गया। इसने मनरेगा को पूरी तरह से नहीं बल्कि एक व्यापक आर्थिक स्थिरता के कारक के तौर पर काम करने दिया। नए अधिनियम के तहत, इस तर्क को मौलिक रूप से कमजोर कर दिया गया है। वीबी-जी राम जी के तहत राज्य-वार मानक आवंटन की पेशकश की गई है जिसमें अतिरिक्त मांग की फंडिंग राज्यों को करने की आवश्यकता होगी।

इसका मतलब है कि केंद्र सरकार से वित्तीय जोखिम लेकर उन राज्यों को दिया जा रहा है जो उसे झेलने में कम सक्षम हैं। इससे राज्यों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। मुश्किल समय में, गरीब राज्य खर्च बढ़ाने के बजाय काम कम कर सकते हैं, योजनाओं को मंजूरी देने में देरी कर सकते हैं या नियमों को और सख्त कर सकते हैं। इससे उप-राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक अस्थिरता का खतरा बढ़ सकता है, जिससे संकट के समय राहत कार्य उल्टी दिशा में जा सकते हैं। मनरेगा के तहत जो योजना मांग के अनुसार मदद करने के लिए बनाई गई थी, वह वीबी-जी राम जी के तहत एक सीमित योजना बनकर रह सकती है।

इस योजना में 60 दिन का जो मौसमी ब्रेक दिया गया है वह भी ठीक नहीं लगता। यह इस गलत सोच पर आधारित है कि बोआई और कटाई के समय हर जगह श्रम बाजार में कामगारों की कमी हो जाती है। भारत में, ग्रामीण श्रम बाजार अलग-अलग हिस्सों में बंटा हुआ है और अक्सर काम की कमी के साथ-साथ परिवारों की आर्थिक स्थिति भी नाजुक होती है।

अनुभवजन्य रिपोर्ट से पता चला है कि भूमिहीन परिवारों, महिला श्रमिकों और स्वास्थ्य या कर्ज से जूझ रहे लोगों के लिए, मनरेगा खेत में काम का विकल्प नहीं था, बल्कि ये एक सुरक्षा कवच था, जब आय के अन्य स्रोत विफल हो जाते थे। वीबी-जी राम जी का कैलेंडर आधारित काम का निलंबन उन परिस्थितियों को सीमित करता है जिनमें यह योजना कारगर हो सकती है जिससे परिवारों को एक साथ कई झटकों का सामना करने पर इसकी मदद करने की क्षमता कम हो जाती है।

सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि वीबी-जी राम जी ज्यादा कार्यदिवस देगी या बेहतर परिसंपत्तियों का सृजन करेगी बल्कि यह है कि यह किस तरह के राज्य की कल्पना करता है और बनाता है। नया ढांचा प्रशासनिक दूरदर्शिता और नियंत्रण को लेकर ज्यादा आश्वस्त दिखता है। लेकिन यह आत्मविश्वास तभी ही हो सकता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में जहां झटके अधिक बार और असमान हो रहे हैं वहां लचीलापन पहले से योजना बनाने से ज्यादा, संकट आने के बाद तुरंत और बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता पर निर्भर करता है।

एक ग्रामीण रोजगार व्यवस्था जो बदलाव के मुकाबले निश्चितता को अधिक महत्त्व देती है वह सामान्य समय में तो ठीक से काम कर सकती है, लेकिन मुश्किल समय आने पर दबाव में आ सकती है। वीबी-जी राम जी की असली परीक्षा यह होगी कि क्या यह योजना बुरे समय में भी स्थिरता का सहारा बनती है या सिर्फ अच्छे समय में अधिक कुशलता से काम करती है।

(लेखक भारतीय प्रबंध संस्थान, रांची में अर्थशास्त्र और लोक नीति के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ये उनके निजी विचार हैं)

पर्यावरण संरक्षण में गांधी का नजरिया कितना प्रासंगिक

यहां स्कैन करें

कुमार प्रशांत | वरिष्ठ पत्रकार

अरावली की नई परिभाषा से उपजे विवाद ने पर्यावरण की बहस को आम लोगों तक पहुंचा दिया है। पर्यावरण की लड़ाई आज पूरे संसार में स्वायत्त समाज के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में बदल गई है। इसे पहचानने के लिए द्राविड़ प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है, अपने ही गांधी (महात्मा गांधी) के कहे को उलटने-पलटने की जरूरत है। बहुत पीछे हम न भी जाएं, तो 1920 से वह लगातार दानवी विकास से सीधी लड़ाई में लगे मिलते हैं। वह देश की राजनीतिक आजादी के लिए प्राणपन से जूझते हुए भी, मनुष्य की स्वायत्त जिंदगी की लड़ाई को कमजोर पड़ने नहीं देते हैं।

जिस बात को समझने और कहने की हिम्मत हम आज भी नहीं दिखा पा रहे, निहत्थे व गुलाम देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए महात्मा गांधी ने वह बात कही थी और इस तरह कही कि उनका कहा वक्त की सलीब पर आज भी दीपता है। गांधी ने कहा, 'ये राष्ट्र (यूरोप व अमेरिका) संसार की तथाकथित कमजोर और असंगठित जातियों का शोषण करने में समर्थ हैं...। मैं साफ शब्दों में अपना यह विश्वास जाहिर कर देना चाहता हूं कि बड़े पैमाने पर माल तैयार करने का पागलपन ही आज के विश्व-संकट के लिए जिम्मेदार है। उद्योग (आप इसे अविवेकी विकास पढ़ें) मानव-जाति के लिए अभिशाप बन जाने वाला है। उद्योगवाद (आज का विकासवाद) सर्वथा इस बात पर निर्भर है कि आपमें शोषण करने की कितनी शक्ति है, विदेशी मंडियां आपके लिए कहां तक खुली हैं और प्रतिस्पर्द्धियों का कितना अभाव है। चूंकि इंग्लैंड के लिए ये बातें दिनोंदिन कम हो रही हैं, इसलिए उनके यहां बेकारों की संख्या रोज बढ़ रही है। जब इंग्लैंड की यह हालत है, तो भारत जैसे विशाल देश के लिए तो औद्योगीकरण से लाभ होने की आशा की ही नहीं जा सकती...क्या आप यह करुण स्थिति नहीं देख रहे कि हम अपने 30 करोड़ बेकारों के लिए काम जुटा सकते हैं, परंतु इंग्लैंड अपने 30 लाख के लिए कोई काम मुहैया नहीं कर सकता। उद्योगवाद का भविष्य अंधकारमय है। यदि उद्योगवाद का भविष्य पश्चिम के लिए अंधकारमय है, तो क्या भारत के लिए वह और भी अंधकारमय नहीं होगा?'

संविधान, न्यायपालिका, समाज, सब गांधी के साथ खड़े होकर कहें कि हमें वह विकास चाहिए ही नहीं, जो एकाधिकार के बिना पंगु है।

12 नवंबर, 1931 को *यंग इंडिया* में यह सब लिखने से पहले भी, कई-कई बार वह ऐसी चुनौती उछालते मिलते हैं। 3 नवंबर, 1921 को गांधी ने *यंग इंडिया* में ही सवाल खड़ा किया था, 'यदि संयोग से कोई एक आदमी किसी यांत्रिक आविष्कार द्वारा भारत की सारी भूमि जोत सके और खेती की तमाम पैदावार पर नियंत्रण कर ले, और यदि करोड़ों लोगों के पास कोई और धंधा न हो, तो वे सब भूखों मरेंगे और निकम्मे हो जाने के कारण जड़ बन जाएंगे, जैसे आज भी बहुत लोग बन गए हैं...।'

गांधी आंखों में आंखें डालकर उस दौर में भी हर आरोप का जवाब देते हैं, 'मुझे आपत्ति स्वयं मशीनों पर नहीं, बल्कि उनके लिए पागल बनने पर है। यह पागलपन श्रम बचाने वाले यंत्रों के लिए है..., यहां तक कि हजारों लोगों को बेकार करके, भूख से मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। मैं भी समय और श्रम बचाना चाहता हूं, मगर मानव-समाज के एक अंश के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए। चरखा-संघ ने सफलतापूर्वक दिखा दिया है कि देहातों में भारत की जरूरत का सारा कपड़ा तैयार किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्र का केवल अवकाश का समय ही कताई और उसके बाद की क्रियाओं में लगाना पड़ेगा। मेरे लिए वह चीज निषिद्ध है, जिसमें सबका हिस्सा न हो।'

यह गांधी उन्नाव की यौन पीड़िता के साथ खड़े दिखते हैं, क्योंकि समाज में शक्ति का एकाधिकार पुरुषों के लिए संरक्षित है। यह गांधी अरावली के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि यह विकास पूंजी के साथ कदमताल करता है। पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाता है, इसलिए जरूरी है कि लोग, समाज, संविधान, न्यायपालिका, सब गांधी के साथ खड़े हों और मुखर होकर कहें कि हमें वह विकास चाहिए ही नहीं, जो विशेषाधिकार व एकाधिकार के बिना पंगु है, गूंगा है। यह नई लक्ष्मण-रेखा है, जो कहती है कि उसकी छाया भी छूने की कोशिश न करना, फिर चाहे वह स्त्री के संदर्भ में हो या पर्यावरण के मामले में।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)